www.tamsasanket.com
वर्षः 06 || अंक 196 || लखनऊ
शनिवार
17 अक्टूबर 2026 || पृष्ठः 08 || मूल्यः ₹2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
https://epaper.tamsasanket.com
दैनिक
तमसा संकेत
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 06:06
सूर्यास्तः 05:37
अधिकतमः 32°00
न्यूनतमः 22°00



पेज 07

विशेष समाचार | सुप्रीम कोर्ट के आवश्यक ... >>पेज 04 | सीएम योगी का आगरा दौरा रद्द ... >>पेज 06 | रणबीर कपूर ने कन्नड़ में की बात..

किसी के लिए प्रदर्शन जरूरी, किसी के लिए मूंगफली बेचना, दावा- रोजाना ₹200 करोड़ का नुकसान

सुप्रीम कोर्ट का सीजेपी का प्रदर्शन रोकने से इनकार

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के व्यापारियों की याचिका पर तत्काल आदेश देने से इनकार कर दिया। याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने प्रदर्शन से जुड़ी अन्य याचिकाओं का जिक्र करते हुए कहा, "कोई प्रदर्शन करना चाहता है, कोई मूंगफली बेचना चाहता है, कोई कानून-व्यवस्था चाहता है, ये सभी बातें आपस में जुड़ी हैं।"



कोर्ट बोला- सभी लोग बेहतर समझदारी दिखाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बेहतर समझदारी दिखाएंगे। हम जानते हैं कि सभी छोटे दुकानदार इन दिनों अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं।

हम जानते हैं कि पूरे परिवारों को किन मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।"



अगर प्रदर्शन से कारोबार में गैरकानूनी रुकावट आती है, तो कोर्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। कारोबार रुकने से कई परिवारों की रोजी-रोटी प्रभावित हो सकती है।

जस्टिस सूर्यकांत
CJI

"याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सेंट्रल पार्क बंद होने से ठेले वालों और छोटे व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। प्रदर्शन के कारण उन्हें नुकसान होने का खतरा है। व्यापारी संगठनों ने त्योहार और शादी के सीजन में मध्य दिल्ली में प्रदर्शन के कारण संभावित कारोबार नुकसान का मुद्दा उठाया है। वहीं अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और 2 पूर्व सीएम समेत 7000 लोगों को भी हिरासत में लिया था। दो जगह पथराव भी हुआ था, जिसमें पुलिस के 7 जवान घायल हुए थे।"

10 अक्टूबरः जंतर-मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी ने SIR के विरोध में और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को धरने का ऐलान किया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने CJP का प्रदर्शन रोक दिया था।

पार्टी की टॉप लीडरशिप अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को विमान से ही हिरासत में ले लिया था।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीनों को रविवार सुबह करीब 10 बजे रिहा करने का आदेश दिया था। तीनों 23 घंटे पुलिस कस्टडी में रहे।

सीजेपी के तिरंगा मार्च पर पुलिस की रोक

अभिजीत दीपके हिरासत में, मैसेज जारी किया

आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क में 'लहरा दो तिरंगा' रैली बुलाई थी। हालांकि आसपास इलाके में धारा 163 लागू थी। जिसके चलते CJP फाउंडर अभिजीत दीपके को वहां जाने नहीं दिया गया। दीपके दिल्ली में NCP-SP के एक प्रवक्ता के घर रुके थे। वह जैसे ही बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को मंडी हाउस से कस्टडी में लिया गया। 6 दिनों में दीपके को दूसरी बार कस्टडी में लिया गया है। इससे पहले 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले दीपके को विमान से हिरासत में लिया गया था, अगले दिन छोड़ दिया गया। हिरासत में लिए जाने से पहले दीपके ने एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा- दिल्ली पुलिस से 7-8 पुलिसवाले आए।

>> (शेष पेज 06 पर)





सरकार इस महीने संसद का स्पेशल सेशन बुला सकती है

लोकसभा सीटें बढ़ाने और परिसीमन बिल पेश करने का अनुमान

आरक्षण

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार इसी महीने संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इसमें लोकसभा सीटें बढ़ाने के लिए संविधान (131वां संशोधन) बिल, परिसीमन (संशोधन) बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल को पास कराया जाएगा। इनके जरिए महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। 6 महीने (16 और 17 अप्रैल) पहले सरकार पहले प्रयास में कामयाब नहीं



रही थी और लोकसभा में दो तिहाई बहुमत जुटा नहीं पाई थी। अब कहा जा रहा है कि सरकार ने संख्याबल जुटा लिया है। विशेष सत्र बुलाने से करीब एक हफ्ते पहले इसकी सूचना दी जा सकती है। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को खत्म हुआ था।

>> (शेष पेज 06 पर)

पिछले सत्र से अभी तक लोकसभा में क्या बदला?

- डीएमके : 'इंडिया' (इंडिया) गठबंधन से औपचारिक रूप से अलग हो गई।
- टीएमसी : पार्टी में बड़ी बगावत हुई और 21 सांसद टूटकर एनसीपीआई (एनसीपीआई) में शामिल हो गए।
- शिवसेना (यूटीबी): 6 सांसदों ने पाला बदलकर अलग गुट बना लिया। एनडीए को समर्थन दिया।



योगी बोले : ये 2-3 सीटों पर लड़ सकते थे, पीडीए यानी पराया धन अपना

'सपा ने राज्यसभा टिकट धन्नासेठ को गिरवी रखा'

बहस

तमसा संकेत, एजेंसी

गाजियाबाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गाजियाबाद में अखिलेश का बिना नाम लिए कहा- राज्यसभा चुनाव में सपा ने कैसे टिकट बेचने का काम किया है, आपने देखा है। वे दो या तीन सीटों पर लड़ सकते थे। लेकिन, मैं पहले दिन से कह रहा था कि सपा के PDA का मतलब- परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने अपना पहला टिकट चचाजान को दिया। भाजपा ने कहा था- PDA का मतलब- पराया धन अपना। ऐसे में उन्होंने दूसरा टिकट मुंबई के धन्नासेठ को गिरवी रख दिया। यही है इनकी असलियत। योगी ने गाजियाबाद के डासना स्थित सुंदरदीप डीम्ड यूनिवर्सिटी में MLC स्नातक और शिक्षक चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित किया। चुनाव में दिनेश कुमार गोयल और श्रीचंद शर्मा प्रत्याशी हैं। दिनेश कुमार गोयल गाजियाबाद और श्रीचंद शर्मा गौतमबुद्धनगर के रहने वाले हैं।

>> (शेष पेज 06 पर)



योगी ने कहा- आज शारदीय नवरात्रि पर कई जगहों पर बड़ी-बड़ी रामलीलाएं चल रही हैं। कहीं उपद्रव नहीं। चारों ओर उत्सव का माहौल होता है। सपा की सरकार होती तो दंगे, कर्फ्यू होते। सपा के समय में ये कांवड़ यात्रा और रामलीलाएं संभव नहीं थी। उस समय नवरात्रि में दुर्गापूजा के पंडाल नहीं लग सकते थे।



'योगी बोले- शिक्षक-स्नातक चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों को जिताएं'

सीएम बोले कि मेरठ खंड में शिक्षक मतदाता और स्नातक मतदाता पहले से ही अपना आशीर्वाद दे चुके हैं। इस बार फिर आप अपना आशीर्वाद देंगे। इसलिए मैं आपके बीच आया हूं। आप सब से मेरी अपील है कि शिक्षक-स्नातक चुनाव में दोनों सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों को जिताकर भेजिए। 23 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग ने अवकाश घोषित किया है।

"योगी ने कहा- सपा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। सपा शिक्षा विरोधी है। शिक्षा पर ये कितना भी बड़ा उद्देश्य दें, जैसे कोई मगरमच्छ नदी किनारे बैठकर किसी से कहे कि आओ मैं पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दूंगा। ये नदी पार कराने वाले नहीं, डिबोने वाले हैं।

'सपा सरकार में विकास कोसों दूर था'

योगी ने कहा- सपा का विकास से कोसों दूर कोई संबंध नहीं है। सपा का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। ये शिक्षा के दुश्मन हैं। सपा को युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। चार बार प्रदेश में सपा की सरकार थी। इनकी सरकार में आपने देखा होगा, सपा ने प्रदेश में संकट ही खड़ा किया। सुरक्षा, विकास, पहचान, रोजगार का संकट था। शिक्षकों के सामने संकट था। सपा सरकार में प्रदेश की पहचान दंगे, कर्फ्यू, लूट, उजड़ी सड़कें, नदारद बिजली थी।



'आज बड़ी रामलीलाएं हो रहीं, सपा सरकार होती तो दंगे होते'

योगी ने कहा- आजम खान विश्वविद्यालय बनाएगा तो उनके लिए सपा सरकार में दूसरे मानक थे। लेकिन, अगर ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनने का प्रयास कर रही है तो उसे मान्यता नहीं देते थे। जब भाजपा की सरकार बनी तो एक जैसा मानक बनाया। सबका साथ और सबका विकास देखना है तो भाजपा सरकार में देखने को मिलेगा।

फास्ट न्यूज

यात्रियों को महंगे फ्लाइट टिकटों से राहत मिलेगी

नई दिल्ली। यात्रियों को महंगे फ्लाइट टिकटों से जल्द ही राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने एयरलाइंस के मनमाने किराए को कंट्रोल करने के लिए नए नियमों को फाइनल कर लिया है। सरकार दो हफ्ते में इन नए नियमों को जारी करेगी।

आईएएस पर महिला अफसर को गाली देने का आरोप

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में एक IAS अधिकारी का महिला अफसर को गाली देने का वीडियो सामने आया है। वर्चुअल मीटिंग में IAS अधिकारी कुमार राजीव रंजन महिला अफसर बेनिश वानी पर चिल्लाते और उन्हें सस्पेंड करने के साथ नौकरी से निकालने की धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। यह घटना मिशन युवा की समीक्षा मीटिंग के दौरान हुई। मीटिंग में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की भूमिका पर चर्चा हो रही थी। उस समय रंजन जम्मू-कश्मीर के श्रम एवं रोजगार विभाग में सचिव के पद पर तैनात थे।

यूपी में आंधी-बारिश, राजस्थान में ओले भी गिरे

नई दिल्ली। यूपी में शुक्रवार सुबह से आगरा, मथुरा और हाथरस समेत 5 शहरों में तेज हवाओं के साथ रुक-रुककर बारिश हो रही है। मौसम खराब होने के चलते मथुरा के सभी स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम बदल गया है।

सीजेआई सूर्यकांत पर टिप्पणी मामले में संजय राउत को नोटिस

विपक्षी नेताओं से नहीं मिलने की आलोचना की थी

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत से CJI सूर्यकांत पर टिप्पणियों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। राउत ने चुनाव आयोग के कामकाज और SIR के मुद्दे पर INDIA ब्लॉक के नेताओं से मिलने से इनकार करने पर CJI की आलोचना की थी। पत्रकार निखिल वागले को भी नोटिस जारी किया है।

यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की आपराधिक अवमानना याचिका पर हुई है। कोर्ट ने कहा कि संस्थानों पर हमले अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। दोनों से पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। सुप्रीम



कोर्ट ने सांसद संजय राउत और निखिल वागले को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी है। CJI ने कहा था कि मामला याचिका के जरिए अदालत में उठाया जा सकता है। संजय राउत और निखिल वागले ने CJI के इस फैसले की आलोचना की थी।

12 अक्टूबर को राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था और SIR के विरोध में 13 याचिकाएं दाखिल की थीं।

>> (शेष पेज 06 पर)

आरोपः भाजपा की साजिश के विरोध में हूं, 100 सीटों की गड़बड़ियों का डेटा चुनाव आयोग को सौंपा

हम एसआईआर या एसएसआर के विरोध में नहीं : अखिलेश

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा-उनकी पार्टी SIR या SSR के विरोध में नहीं है, बल्कि इसमें कथित साजिश और गड़बड़ी के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि वोटर लिस्ट का एक ही रिवीजन होना चाहिए। बार-बार रिवीजन नहीं होना चाहिए। नाम जोड़ने या काटने की प्रक्रिया इसी दौरान पूरी कर ली जाए। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय



सपा ने अनोखे अंदाज में सरकार का विरोध किया।

पर पूर्व सीएम ने प्रेस कांफ्रेंस की।

>> (शेष पेज 06 पर)



अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने 100 विधानसभा क्षेत्रों का डेटा चुनाव आयोग को सौंपा है। उन्होंने एक ऐसे युवक का जिक्र किया, जो पहली बार वोट डालने वाला है, लेकिन उसके नाम कई जगह दर्ज होने का दावा किया गया है।

एक युवक के कई जगह वोट बनने का दावा

अखिलेश ने कहा कि युवक पढ़ने वाला और ईमानदार है। वह एक ही जगह वोट डालेगा, लेकिन बाकी जगह उसके नाम पर दूसरे लोग वोट डाल सकते हैं। उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि SIR के दौरान 20 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की जान जाने का मुद्दा भी सामने आया था। अखिलेश ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सबूत सामने आने पर उन्हें छोटी-मोटी गलती बताकर टालने की कोशिश की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा पर अफसरों को चेतावनी

कहा-काम नहीं हुआ तो हाईकोर्ट के गेट पर धरना देंगे

अर्लट

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के पास सड़क पार करने वाले लोगों की सुरक्षा के मामले में अधिकारियों को चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि अगर काम पूरा नहीं हुआ, तो दोनों जज दिल्ली हाईकोर्ट के गेट पर धरने पर बैठ जाएंगे और काम पूरा होने तक घर नहीं जाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) बनर्जी को भी घर नहीं जाने दिया जाएगा। यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के पास सड़क पार करने वाले लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को केंद्र सरकार से कहा था कि वह



दिल्ली हाईकोर्ट और नेशनल जूलॉजिकल पार्क के पास सड़क पार करने वाली जगह पर स्पीड ब्रेकर और रंबल स्ट्रिप्स लगाने पर फैसला ले। सुनवाई के दौरान कोर्ट की मदद के लिए नियुक्त एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने उस जगह रेड लाइट सिग्नल लगवा दिया है। केवल रेड लाइट लगाना काफी नहीं है। वहां स्पीड ब्रेकर और रंबल स्ट्रिप्स लगाने की जरूरत है।

>> (शेष पेज 06 पर)

विपक्ष का एजेंडा- देश में आतंकी पैदा करना और बांग्लादेश की तरह सरकार बदलना

राहुल युवाओं को भटका रह : राजनाथ

देश के युवाओं को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार को डंके की चोट पर गिराने की बात करते हैं। इससे साफ है कि उनका एकमात्र एजेंडा लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करना और देश में आग लगाना है।

सत्ता हासिल करने की साजिश रची जा रही है

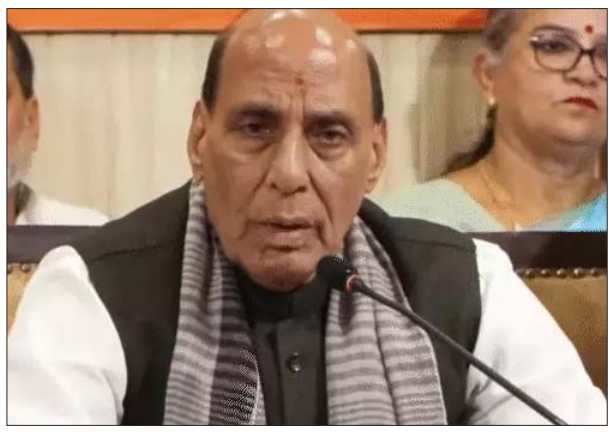
'Regime Change' जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना साफ करता है कि उनकी लड़ाई चुनाव सुधार के लिए नहीं है। उनकी लड़ाई SIR और ज्ञानेश कुमार के लिए नहीं है और न ही उनकी लड़ाई देश के नौजवानों के उज्ज्वल भविष्य के लिए है। बल्कि, यह लड़ाई देश में अराजकता पैदा करने और किसी भी तरह सत्ता हासिल करने की साजिश का हिस्सा है।

कार्यक्रम

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें दिल्ली में हुए प्रदर्शनों पर सवाल उठाए। राजनाथ ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल युवाओं को भटका रहे हैं। बांग्लादेश की तर्ज पर देश में जबरन सरकार बदलना चाहते हैं। उनका एजेंडा लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करना और देश में आतंकी पैदा करना है।

राजनाथ ने राहुल गांधी से पूछा- क्या आप बिना सपा के समर्थन के अपनी रायबरेली सीट जीत पाएंगे। कांग्रेस 37 साल से यूपी की सत्ता से बाहर है। यह वोट चोरी के कारण नहीं, बल्कि काम चोरी के कारण है।



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में हुई मारपीट पर राजनाथ ने कहा- कांग्रेस के लोगों को खुद ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, तभी वो आपस से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। उनका इशारा लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में रविवार को पार्षद ममता चौधरी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के समर्थकों के बीच हुई बहस और मारपीट की तरफ था।

यूपी में 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कुल 80 सीटों में से सपा ने 63 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें रायबरेली और अमेठी की सीट भी शामिल हैं। रायबरेली से राहुल और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा ने जीत हासिल की थी। राहुल ने वोट चोरी को हाइड्रोजन बम बताया था, लेकिन वह पटाखा भी साबित नहीं हुआ।

कांग्रेस के इतिहास के पन्ने में कई काले अध्याय

कांग्रेस के इतिहास के पन्ने में कई काले अध्याय मिलेंगे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया को कठपुतली बनाकर रखा। 1993 में रातों-रात 2 नए चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा। नवीन चावला को कांग्रेस ने बचाया और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया।

चुनाव आयुक्त एमएस गिल कांग्रेस सरकार में मंत्री बने

कांग्रेस राज में नियुक्त चुनाव आयुक्त एमएस गिल कांग्रेस सरकार में मंत्री बने थे। 5 दशक तक बिना वोटर आईडी के चुनाव होते थे। जब से वोटर आईडी आया है, कांग्रेस के लिए बहुमत दूर की बात हो गई है। कांग्रेस ने कभी बहुमत की सरकार नहीं बनाई। यूपी में कांग्रेस को 1985 में आखिरी बार जीत मिली थी।

ऑक्सीजन सिलेंडर लदी पिकअप डिवाइडर से टकराई, 2 की मौत

टक्कर के बाद केबिन में फंसे थे दोनों

तमसा संकेत, एजेंसी



मोहनलालगंज । लखनऊ में शुक्रवार शाम ऑक्सीजन सिलेंडरों से लदी एक पिकअप डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि पिकअप में सवार तीसरे व्यक्ति को भर्ती कराया गया है। पिकअप का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद चालक समेत दो लोग केबिन में फंस गए। सूचना पर पहुंची निगोहां पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को बाहर निकाला।

इसके बाद उन्हें मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया, जहां ड्राइवर और परिचालक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसा निगोहां क्षेत्र में शेखपुरा टोल प्लाजा के पास हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप में लदे ऑक्सीजन सिलेंडर सड़क पर बिखर गए। मृतकों की पहचान इंद्रजीत पटेल (55) और रमेश चंद्र के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे निगोहां पुलिस को सूचना मिली कि शेखपुरा टोल प्लाजा के पास ऑक्सीजन सिलेंडरों से लदी पिकअप डिवाइडर से टकरा गई है। सूचना मिलते ही निगोहां थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पिकअप डिवाइडर से टकराई हुई मिली, जबकि उसमें लदे सिलेंडर सड़क पर चारों तरफ बिखरे पड़े थे। टक्कर के कारण पिकअप का अगला हिस्सा दब गया था।

फास्ट न्यूज

दुर्गा पूजा में डांडिया की धुन पर झूमीं महिलाएं

लखनऊ । लखनऊ के जानकीपुरम स्थित सहारा स्टेट शहर दुर्गा पूजा में संगीत की धुन शुरू होते ही कदम थिरकने लगे। हाथों में डांडिया स्टिक लिए महिलाएं गोल घेरे में आईं और ताल से ताल मिलाकर गरबा किया। रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधान, गुजराती गीतों की धुन और डांडिया की खनक से सहारा स्टेट्स में आयोजित गरबा नाइट की शाम उत्सव के रंग में रंग गई।

जैन मंदिर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान शुरू

लखनऊ। लखनऊ के गोमती नगर स्थित जैन मंदिर में आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज के ससंघ सानिध्य और पंडित अरविन्द शास्त्री के निर्देशन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन 16 से 21 अक्टूबर तक किया जा रहा है। शुक्रवार को पहले दिन भगवान का अभिषेक, शांतिधारा, महिलाओं की घट यात्रा और सिद्ध चक्र पूजन विधान हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेकर पूजा-अर्चना की। आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज ने प्रवचन में बताया कि सिद्ध चक्र विधान सिद्धों की आराधना और आत्मकल्याण का महत्वपूर्ण धार्मिक माध्यम है।

फैजुल्लागंज बाढ़ का प्रभारी मंत्री ने किया निरीक्षण

लखनऊ । लखनऊ के फैजुल्लागंज इलाके में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से गंभीर जलभराव की स्थिति बन गई है। इस आपदा से क्षेत्र के लगभग 6,500 घर और 50 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शुक्रवार को फैजुल्लागंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया।

कविताओं के जरिए राजनीति पर प्रहार, वीर रस से गूंजा पंडाल

तमसा संकेत, संवाददाता



सूरतगंज (बाराबंकी)। नवरात्र की भक्ति के बीच जब कवियों ने शब्दों के बाण चलाए तो कभी पंडाल ठहाकों से गूंज उठा, तो कभी राष्ट्रभक्ति की रचनाओं ने श्रोताओं में जोश भर दिया। मां की ममता, प्रेम की संवेदना और किसानों की समस्याओं को स्वर देती कविताओं ने साहित्य प्रेमियों को भावविभोर कर दिया। मौका था सूरतगंज क्षेत्र की जफरपुर ग्राम पंचायत में नवदुर्गा जागरण के पांचवें दिन आयोजित भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का। देर रात तक चले इस साहित्यिक आयोजन में कवियों ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियों से श्रोताओं को बांधे रखा।नवदुर्गा जागरण समिति के अध्यक्ष अजय सिंह राठौर की अगुवाई में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कवियों ने हास्य-व्यंग्य, वीर रस, श्रृंगार, भक्ति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रचनाएं प्रस्तुत कीं। मां दुर्गा के जयकारों के बीच कविता और साहित्य का ऐसा रंग जमा कि श्रोता देर रात तक पंडाल में डटे रहे। राजनीति पर किए गए इस व्यंग्य ने श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। रचना की पंक्तियों पर पंडाल तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। हास्य के साथ सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर सवाल उठाने वाली इस प्रस्तुति ने कार्यक्रम में खास रंग भर दिया।

वीर रस के कवि डॉ. पवन त्रिवेदी 'अंगार' ने अपनी ओजपूर्ण प्रस्तुति से श्रोताओं में राष्ट्रप्रेम का भाव जगाया। उन्होंने महाराणा प्रताप और वीरता व बलिदान के प्रतीकों का स्मरण कराते हुए पंक्तियां पढ़ीं

उनकी ओजस्वी वाणी और वीर रस से ओतप्रोत रचना पर श्रोताओं ने तालियों के साथ उत्साह जताया।

राजनाथ की पीसी में दूसरी पंक्ति में दिखीं मेयर, पार्टी नेताओं से नाराजगी के संकेत

भाजपा मुख्यालय में मेयर सुषमा खर्कवाल को पीछे बैठाया

तमसा संकेत, एजेंसी



लखनऊ। शुक्रवार, 16 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल को पहली पंक्ति के बजाय दूसरी पंक्ति में सुरक्षाकर्मियों के साथ बैठाया गया। जबकि, मंच पर पहली लाइन में राजनाथ सिंह के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह और मीडिया संयोजक मनीष दीक्षित बैठे थे।

जानकारों के मुताबिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेयर के कामकाज से खुश नहीं हैं। वहीं, मेयर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच भी राजनीतिक खींचतान की चर्चा है। लखनऊ के कई भाजपा विधायक और पार्षद भी मेयर से नाराज बताए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि मेयर उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेतीं। नगर निगम के कामकाज में ढिलाई और लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देने को लेकर भाजपा के कई विधायक पार्टी के बड़े नेताओं को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। मेयर और जनप्रतिनिधियों के बीच इस नाराजगी और खींचतान का मामला कई बार दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक भी पहुंच चुका है।

मेयर और पार्षदों के बीच फंड को लेकर भी भारी खींचतान चल रही है। अगस्त महीने में एक दर्जन से ज्यादा पार्षदों ने मेयर पर विकास कार्यों के लिए बजट न देने का गंभीर आरोप लगाया था। दरअसल, लखनऊ नगर निगम में इसी साल मई में 68 करोड़ 66 लाख रुपए का बजट पास किया गया था। इसमें अवस्थापना निधि के 55.40 करोड़ रुपए और 15वें वित्त आयोग से मिले 13 करोड़ रुपए शामिल थे। ये फंड पार्षदों को मिलने वाले सालाना 2.10 करोड़ रुपए के विकास फंड से अलग था।



ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है। मंच पर मेयर सुषमा खर्कवाल पीछे बैठी हैं। किसी को फोन लगाती दिख रही हैं।

महानगर अध्यक्ष को कुर्सी तक नहीं मिली

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लखनऊ महानगर भाजपा अध्यक्ष आनंद द्विवेदी को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई। पूरे कार्यक्रम के दौरान वे सुरक्षा कर्मियों के साथ खड़े ही रहे। इसे लेकर भी संगठन के अंदर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के अधिकारी हमेशा शीर्ष नेताओं के साथ पहली पंक्ति में दिखाई देते हैं।

आरोपों पर मेयर का कहना है कि विकास फंड का आवंटन जरूरत के हिसाब से किया जाता है और किसी भी वार्ड के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। उन्होंने पार्षदों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि कुछ पार्षद किसी राजनीतिक दबाव या इशारे पर उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं।

लखनऊ में मां ने कहा था- बेटी ने शादी से मना किया तो धक्का देकर हत्या की

गर्लफ्रेंड की होटल से गिरकर मौत, बॉयफ्रेंड का सरेंडर





तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ । लखनऊ के समरीन हत्याकांड में फरार बॉयफ्रेंड ने सरेंडर कर दिया है। आरोपी अवनीश जायसवाल उर्फ देव गुरुवार शाम अपने वकील के साथ ACJM कोर्ट पहुंचा। जहां कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे हिरासत में ले लिया गया।

एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए जल्द ही कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। रिमांड के बाद पुलिस उससे पूछताछ शुरू करेगी और जल्द से जल्द मामले का खुलासा करेगी।

24 साल की समरीन की सोमवार शाम 6.30 बजे होटल सेलेस्टियल मैन्योर की 10वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। वह अवनीश के साथ रुकी थी। उसके गिरने के बाद अवनीश भाग गया था। दोनों ने होटल में दोपहर 12 बजे चेक-इन किया था।

समीरन की मां ने आरोप लगाया था कि अवनीश बेटी पर शादी का दबाव बना रहा था। मना करने पर उसने समरीन को धक्का देकर नीचे फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समरीन की मौत का कारण गंभीर चोटों के चलते शॉक और हैमरेज बताया गया। ऊंचाई से गिरने से उसकी कमर और दोनों पैर टूट गए थे। सिर में गंभीर चोट आई थी।

दिन में दोनों होटल आए शाम को लड़की गिरी

पुलिस के मुताबिक, समरीन लखनऊ की ही रहने वाली थी। अवनीश उर्फ देव सुल्तानपुर की दोस्तपुर नगर पंचायत के मोहल्ला फिरोजपुर खुर्द का रहने वाला है। समरीन एक होटल में काम करती थी और शादीशुदा थी। उसका पति से तलाक का केस चल रहा है। इसे लेकर सोमवार को पेशी थी, लेकिन वह नहीं गई। वह सुबह 11 बजे बहन हबीबा के लिए कपड़े लेने की बात कहकर घर से निकली थी।

अवनीश ने होटल का कमरा नंबर-1037 बुक कराया था। वह सोमवार दोपहर 12 बजे समरीन के साथ होटल पहुंचा। शाम 6 बजे समरीन बालकनी से नीचे गिर गई। यह देखकर देव दौड़कर लिफ्ट में घुस गया। इसके बाद वह ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकला, फिर पार्किंग से अपनी बाइक लेकर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची। सबूत इकट्ठा किए। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।

'84 लाख आवेदन के मुकाबले 71 लाख फॉर्म-6 ही सार्वजनिक'

संजय सिंह का आरोप- वोट चोरी की तैयारी कर रही भाजपा

तमसा संकेत, एजेंसी



लखनऊ । आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर के बाद नए वोटरों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि नाम जोड़ने के लिए 84 लाख आवेदन आए, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल 71 लाख फॉर्म-6 ही सार्वजनिक किए।

उन्होंने पूछा कि बाकी 13 लाख नाम किस आधार पर जोड़े गए। संजय सिंह ने इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा। साथ ही भाजपा पर वोट चोरी की तैयारी करने का आरोप लगाया।

संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। एसआईआर के बाद करीब 2 करोड़ 90 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने का दावा करते हुए उन्होंने बताया कि नाम जोड़ने के लिए 84 लाख और नाम हटाने के लिए 4 लाख 30 हजार आवेदन आए। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों के आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया का पूरा ब्योरा सामने आना चाहिए। आप सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक फॉर्म-6 का विवरण सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि राजनीतिक दलों को पता चल सके कि किस विधानसभा क्षेत्र और किस बूथ पर किन मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 84 लाख आवेदन आए तो केवल 71 लाख फॉर्म-6 ही सार्वजनिक क्यों किए गए?

आरोप : मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग, पीसीएफ बिल्डिंग पर हंगामा

राजधानी में आजाद समाज पार्टी की पुलिस से धक्का-मुक्की

तमसा संकेत, एजेंसी



लखनऊ । लखनऊ में शुक्रवार को आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हुसैनगंज स्थित PCF बिल्डिंग पर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की और नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाया।

प्रदेश सचिव अनिकेत धानुक ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने लोकतंत्र की हत्या की है। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि 35 करोड़ से ज्यादा वोटों की चोरी कर अलग-अलग राज्यों और केंद्र में भाजपा की सरकार बनवाने में मदद की गई। अनिकेत धानुक ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके इशारे पर पूरा चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। प्रदर्शनकारी अनिकेत ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, भाजपा का पिट्ठू बन चुका है लगातार बेमानी करवा रहा है। इन लोगों ने पहले बिहार और पश्चिम बंगाल लूटा अब उत्तर प्रदेश को लूटने की तैयारी कर रहे हैं।



'राजा की जान तोते में'

प्रदर्शन कर रहे अमन कुमार धानुक ने कहा ज्ञानेश कुमार ने हमसे वोट का अधिकार छीना है इसलिए हम उनका इस्तीफा लेने आए हैं। जब तक इस्तीफा नहीं हो जाएगा हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जैसे राजा राजा की जान तोते में होती है वैसे ही मोदी की जान ज्ञानु में है। आज हम लोग यहां प्रदर्शन कर रहे हैं । अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी जाएंगे हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद लगातार वोट चोरी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

महिलाओं की सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम

लखनऊ । लखनऊ के तेलीबाग स्थित राम भरोसे मैकूलाल महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई की ओर से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तीकरण के प्रति जागरूकता के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्राओं को महिला सुरक्षा और आपातकालीन सहायता सेवाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम, लैंगिक समानता, बालिका शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज में महिलाओं की भागीदारी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। छात्र-छात्राओं को बताया गया कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। छात्राओं को किसी भी तरह के उत्पीड़न या हिंसा की स्थिति में निर्भीक होकर शिकायत करने और उपलब्ध सहायता सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने किया।

समान वेतन की मांग को लेकर किया था प्रदर्शन, 70-80 अज्ञात पर केस दर्ज

बॉन्डेड डॉक्टरों पर एफआईआर

तमसा संकेत, एजेंसी



लखनऊ । लखनऊ में समान वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बॉन्डेड MBBS डॉक्टरों के खिलाफ हजरतगंज पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक, 14 अक्टूबर को विधानसभा के पास अटल चौक स्थित गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन के दौरान 70-80 डॉक्टरों ने सड़क जाम कर दिया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने सरकारी काम में बाधा डाली और पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की।

दरअसल, गुरुवार को डॉक्टरों ने समान वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गले में स्टेथोस्कोप और मुंह पर टेप लगाकर पहुंचे डॉक्टरों ने पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाई। कुछ डॉक्टर सड़क पर लेट गए। डॉक्टरों ने 1090 चौराहे से चेन बनाकर सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। डॉक्टरों को सड़क पर बैठा देख ACP भी जमीन पर बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर डॉक्टरों से धरना खत्म करने की अपील की।

सचिवालय चौकी प्रभारी उप-निरीक्षक (SI) बागेश कुमार द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, 14 अक्टूबर 2026 की सुबह लगभग 10 बजे 70 से 80 अज्ञात व्यक्ति जिनमें कुछ डॉक्टर की पोशाक में और हाथों में तख्तियां-बैनर लिए हुए थे। अचानक गांधी प्रतिमा के सामने फुटपाथ पर जमा हो गए। वे मानदेय विसंगतियों को दूर करने और समान वेतन का आश्वासन मिलने को लेकर उप-मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को समझाया कि यह क्षेत्र विधानसभा व लोक भवन के पास है। प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहां धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। हालांकि, प्रदर्शनकारी और अधिक उग्र हो गए और मुख्य सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

पुलिस ने सड़क खाली कराने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से अभद्रता की। इसके बाद वे जीपीओ (GPO) के सामने रोड और फुटपाथ पर बैठ गए।

17 और 24 अक्टूबर को लगेंगे विशेष कैंप, 4 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा

1200 से ज्यादा वोटर वाले बूथों पर नया केंद्र बनेगा

बैठक

तमसा संकेत, एजेंसी

बाराबंकी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बाराबंकी में मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। शुक्रवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान और मतदेय स्थलों के पुनर्गठन की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने और निर्धारित समयसीमा के भीतर पुनरीक्षण की



प्रक्रिया पूरी करने पर चर्चा हुई। निर्वाचन विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन से संबंधित दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन के बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इस अवधि में मतदाता सूची से संबंधित त्रुटियों को दूर करने और आवश्यक संशोधन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद संशोधित मतदाता सूची तैयार कर अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निर्वाचन कार्यक्रम के मुताबिक, बाराबंकी में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को निर्धारित किया गया है। इसके लिए पुनरीक्षण से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं तय समयसीमा के भीतर पूरी की जाएंगी।

66 जिलाधिकारी ने युवाओं और पहली बार मतदाता बनने वाले नागरिकों से कैंप में पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से सूची में अपना नाम जांचने और जरूरत के अनुसार संशोधन कराने को भी कहा, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।



1200 से ज्यादा मतदाताओं वाले बूथों का होगा पुनर्गठन

बैठक में बताया गया कि 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदेय स्थलों पर नया बूथ बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। मतदेय स्थलों की सूची का आलेख्य प्रकाशन 19 अक्टूबर को होगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि 26 अक्टूबर तक सुझाव और आपत्तियां दे सकेंगे। इसके बाद 27 अक्टूबर तक प्रस्ताव भेजे जाएंगे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदेय स्थलों का पुनर्गठन निर्धारित मानकों के अनुसार समय से पूरा किया जाए। साथ ही मतदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने राजनीतिक दलों से सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने की अपील भी की।

17 और 24 अक्टूबर को लगेंगे विशेष कैंप

जिले के सभी मतदेय स्थलों पर 17 और 24 अक्टूबर को विशेष मतदाता पंजीकरण कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र नागरिकों को फॉर्म-6 भरना होगा। आवेदन के साथ नवीनतम फोटो और जन्मतिथि व पते से संबंधित जरूरी दस्तावेज देने होंगे।

आईडीबीआई बैंक की बिक्री के विरोध में बैंक-कर्मियों का प्रदर्शन

काली पट्टी बांधकर सरकार के फैसले के खिलाफ जताई नाराजगी

तमसा संकेत, एजेंसी

हरदोई। हरदोई जनपद में आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी (LIC) की हिस्सेदारी कनाडा की निजी कंपनी 'फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स' को बेचने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक कर्मचारियों का आक्रोश फूट पड़ा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) की हरदोई इकाई के आह्वान पर शुक्रवार की सुबह 10 बजे बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी बाँहों पर काली पट्टी और विरोध बैज लगाकर सरकार की इस निजीकरण नीति के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। यूएफबीयू ने सरकार के इस कदम को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग ढाँचे, जनसाधारण की मेहनत की कमाई और देश की आर्थिक संप्रभुता पर बड़ा हमला करार दिया है। बैंक



यूनियनों ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि जिस आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी की लगभग 94 फीसदी हिस्सेदारी है। जहां आम जनता का 3.50 लाख करोड़ का विश्वास (जमा राशि) सुरक्षित है और जो बैंक बीते तीन सालों में 22,600 करोड़ का शानदार शुद्ध लाभ कमा चुका है, उसे किसी विदेशी निजी निवेशक की झोली में डालने का औचित्य समझ से परे है। यूनियन प्रतिनिधियों ने याद दिलाया कि वर्ष 2003 में जब आईडीबीआई को बैंकिंग कंपनी में बदला गया था, तब संसद के पटल पर सरकार ने हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम न करने का वादा किया था। आज का यह फैसला उस ऐतिहासिक आश्वासन की खुली अवहेलना है। इसके अलावा, निजीकरण के बाद बैंक में लागू अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पूर्व सैनिकों के आरक्षण का भविष्य भी अधर में लटक जाएगा।

एक तरफ सरकार 'आत्मनिर्भर भारत' का नारा देती है और दूसरी तरफ देश के प्रमुख बैंक की चाबी विदेशी हाथों में सौंप रही है, जो परस्पर विरोधाभासी है। सार्वजनिक बैंक सिर्फ मुनाफे का जरिया नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बैंक कर्मियों का यह काली पट्टी प्रदर्शन जनहित और सार्वजनिक बैंकिंग की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। यूएफबीयू ने चेतावनी दी है।

फास्ट न्यूज

ट्रेन की चपेट में आने से संविदा कर्मी की मौत

उन्नाव। उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से एक 55 साल के व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की पहचान लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के रहीमनगर परियाना निवासी रामफूल राजपूत के रूप में हुई है। उनके परिवार में इस घटना से दुख का माहौल है। जानकारी के मुताबिक, रामफूल राजपूत रेलवे में निजी तौर पर काम करते थे। वह रेलवे ट्रैक पर गिट्टी हटाने का काम करते थे। अजगैन इलाके में काम के दौरान ही वह ट्रेन की चपेट में आ गए।

चंडीगढ़ से हरदोई लाई गई 13 साल की किशोरी

हरदोई। चंडीगढ़ के एक आवासीय स्कूल से निकली करीब 13 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर हरदोई लाने और उसकी जबरन शादी कराने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि किशोरी को पहले एक अधेड़ व्यक्ति के 40 वर्षीय अविवाहित बेटे से शादी कराने का प्रस्ताव दिया गया। इसके बाद दूसरे परिवार में भी उसकी जबरन शादी कराने का दबाव बनाया गया। बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग के दौरान किशोरी ने आपबीती बताई। इसके बाद एनजीओ कोऑर्डिनेटर की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अस्पताल पर इलाज में लापरवाही और धोखाधड़ी का आरोप

बाराबंकी। बाराबंकी के एक निजी अस्पताल में इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है। देवा थाना क्षेत्र की संगीता देवी ने आस्था हॉस्पिटल पर धोखाधड़ी और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। मामले की जांच सीएमओ बाराबंकी कर रहे हैं। संगीता देवी के मुताबिक, जनवरी 2026 में पेट की बीमारी के इलाज के लिए उनका ऑपरेशन किया गया था।

पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौत

ईंट भट्ठे से घर लौटते समय हुआ हादसा, जांच जारी

तमसा संकेत, एजेंसी

हरदोई। हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र में हरदोई-सांडी मार्ग पर गुरुवार देर शाम तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल मजदूर को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने रात करीब 7:20 बजे उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। कटहैया मजरा अखनापुर निवासी बलवीर (35) पुत्र भगवानदीन ईंट भट्ठे पर मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके बड़े भाई ओमवीर के अनुसार, गुरुवार देर शाम भट्ठे पर काम खत्म करने के बाद बलवीर बाइक से घर लौट रहे थे। गांव के पास हरदोई-सांडी मार्ग पर एक पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार



टक्कर मार दी। आरोप है कि वाहन चालक बलवीर को कुचलते हुए मौके से फरार हो गया। हादसे में बलवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। गंभीर हालत में बलवीर को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां आपातकालीन कक्ष में चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बलवीर की मौत से पत्नी माया और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। वह अपने पीछे तीन बेटियों और एक छोटे बेटे को छोड़ गए हैं।

उन्नाव में पांच थानों में दंपत्तियों की काउंसलिंग

महिलाओं को साड़ी और मां दुर्गा की प्रतिमा देकर किया सम्मानित

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव में परिवार में छोटी-छोटी बातों पर होने वाले विवाद कई बार पति-पत्नी के रिश्तों में दूरियां बढ़ा देते हैं। ऐसे में संवाद और समझाइश की पहल टूटते रिश्तों को फिर जोड़ने में मददगार बन सकती है। मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के छठे दिवस पर शुक्रवार को जिले के पांच थानों में पुलिस ने इसी दिशा में पहल की। असोहा, अजगैन, सोहरामऊ, बिहार और गंगाघाट में दंपत्तियों और परिवारों से संवाद किया गया। कहीं पहले सुलह के बाद साथ रह रहे दंपत्तियों से उनके अनुभव जाने गए, तो कहीं काउंसलिंग के जरिए विवाद सुलझाए गए। अजगैन थाने के परिवार परामर्श केंद्र में पहले सुलह-समझौते के बाद साथ रहने लगे 11 दंपत्तियों को बुलाया गया।



पुलिस टीम ने उनके वैवाहिक जीवन, आपसी सामंजस्य और पारिवारिक माहौल के बारे में जानकारी ली। दंपत्तियों ने पुलिस की मध्यस्थता और परामर्श पर संतुष्टि जताई। उन्होंने बताया कि परामर्श के बाद उनके संबंधों में सकारात्मक बदलाव आया है और वे आपसी प्रेम, विश्वास व सौहार्द के साथ जीवन बिता रहे हैं। पुलिस ने उन्हें भविष्य में किसी भी परेशानी पर संपर्क करने के लिए प्रेरित किया। बिहार थाने के परिवार परामर्श केंद्र में पहले सुलह के बाद साथ रहने लगे दंपत्तियों को बुलाकर सम्मानित किया गया। उन्हें साड़ी और मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट की गई। पुलिस ने उनके पारिवारिक जीवन और आपसी तालमेल का फीडबैक लिया। दंपत्तियों ने पुलिस के परामर्श और सहयोग पर संतोष जताया।

असोहा में परिवारों का सम्मान, हेल्पलाइन की जानकारी दी

असोहा थाने में विभिन्न परिवारों की काउंसलिंग कर पुलिस की सेवाओं और महिला सुरक्षा के प्रयासों पर फीडबैक लिया गया। परिवारों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। सभी पांच थानों में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान महिला पावर लाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181, साइबर हेल्पलाइन 1930, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की जानकारी दी गई।



सोहरामऊ और गंगाघाट में बातचीत से सुलझाए विवाद

सोहरामऊ थाने में मिशन शक्ति टीम ने पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद में दोनों पक्षों की बात धैर्यपूर्वक सुनी। काउंसलिंग के दौरान उन्हें आपसी संवाद, विश्वास और पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने की सलाह दी गई। पुलिस के प्रयासों से दोनों के बीच सहमति बनी और उन्होंने भविष्य में प्रेम, सम्मान व सहयोग के साथ वैवाहिक जीवन बिताने पर सहमति जताई। गंगाघाट थाने की महिला हेल्प डेस्क पर भी पति-पत्नी के विवाद को बातचीत और समझाइश के जरिए सुलझाया गया।

गैस कंपनियां वितरकों को जबरन बेच रहीं उत्पाद

5-10 किलो के सिलेंडर और अन्य सामान भेजने का आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव में एलपीजी वितरकों ने गैस कंपनियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कंपनियां समझौते के खिलाफ जबरन उत्पाद बेच रही हैं। शुक्रवार को वितरकों ने सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि कंपनियां उनकी मांग बदले बिना 5 और 10 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर जबरन भेजती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। शिकायत में बताया गया कि गैस चूल्हा, रबर पाइप, लाइटर, एप्रन, चायपत्ती और पानी जैसे उत्पाद भी जबरन बिकवाए जाते हैं। इन सामानों





की बिक्री का समझौता न होने पर भी कंपनियां इनकी कीमत वितरकों के लोड खाते से काट लेती हैं। साथ ही, 19 किलोग्राम के एनडी सिलेंडरों की आपूर्ति भी जरूरत से ज्यादा की जाती है, जिससे वितरकों को परेशानी होती है। वितरकों ने मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस (एमडीजी) को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मूल समझौते में इसका उल्लेख नहीं है और इसके लिए अलग से हस्ताक्षर कराए गए हैं। आरोप है कि एमडीजी का हवाला देकर वितरकों पर दबाव बनाया जाता है। वितरकों ने जिला पूर्ति अधिकारी से सभी बिंदुओं की जांच कराकर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित गैस कंपनियों का पक्ष सामने नहीं आया है।

ज्यादा हिस्सा गिरवाने और दुकान खाली कराने लगा आरोप, डीएम से शिकायत

सड़क चौड़ीकरण में गिरी दुकान पर हुआ विवाद



तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव में शुक्लागंज के गांधी नगर स्थित पोनी रोड पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान दुकान का हिस्सा गिराए जाने को लेकर मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद सामने आया है। किरायेदार महेंद्र शर्मा ने मकान मालिक पर पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर दुकान का अधिक हिस्सा गिरवाने का आरोप लगाया है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और मामले में न्याय की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि मकान मालिक अब जबरन दुकान खाली कराने का दबाव बना रहा है और विरोध करने पर धमकी दी जा रही है। महेंद्र शर्मा के मुताबिक, वह



गांधी नगर के पोनी रोड स्थित दुकान में किरायेदार के रूप में कारोबार करते हैं। सड़क चौड़ीकरण के दौरान 14 अक्टूबर को दुकान का हिस्सा गिराए जाने को लेकर विवाद बढ़ गया। उनका आरोप है कि चौड़ीकरण के नाम पर दुकान का जरूरत से अधिक हिस्सा गिरा दिया गया। उन्होंने इस कार्रवाई में मकान मालिक की भूमिका होने का दावा करते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है। महेंद्र शर्मा का कहना है कि मकान मालिक और उनके बीच किराये को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। इस

सड़क चौड़ीकरण के दौरान दुकान का हिस्सा गिराए जाने को लेकर मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद।

संबंध में मुकदमा संख्या 165/2024 न्यायालय में विचाराधीन है। किरायेदार का दावा है कि मकान मालिक ने किराया लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय से स्टे मिलने के बावजूद उन पर दुकान खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। किरायेदार ने आरोप लगाया कि 14 अक्टूबर को पोनी रोड पर चौड़ीकरण की कार्रवाई के दौरान उन्हें धमकी दी गई। उनका कहना है कि दुकान को लेकर न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद मकान मालिक लगातार दुकान खाली कराने का प्रयास कर रहा है। इससे उन्हें कारोबार और दुकान की सुरक्षा को लेकर परेशानी हो रही है। शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर महेंद्र शर्मा ने पूरे मामले से संबंधित शिकायत रखी और निष्पक्ष जांच कराकर न्याय दिलाने की मांग की।

कार्यवाई : बाराबंकी एसपी से शिकायत, बच्चेदानी निकालने और 1 लाख रुपए खर्च होने का दावा

अस्पताल पर इलाज में लापरवाही और धोखाधड़ी का लगा आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

बाराबंकी। जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान कथित लापरवाही और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। देवा थाना क्षेत्र की रहने वाली संगीता देवी ने आस्था हॉस्पिटल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। महिला का आरोप है कि जनवरी 2026 में पेट की बीमारी के उपचार के लिए उनका ऑपरेशन किया गया था, लेकिन इसके बाद भी उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर नहीं हुईं। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान इलाज में गड़बड़ी होने और बच्चेदानी निकाले जाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। संगीता देवी ने



इलाज पर करीब एक लाख रुपये खर्च होने का दावा किया है। उनका आरोप है कि अस्पताल में उपचार के दौरान दवाइयों और ब्लड के लिए भी अतिरिक्त पैसे देने पड़े। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इलाज को लेकर विरोध जताने पर उन्हें और उनके पति को धमकी दी गई। शिकायत के बाद मामला स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में है। सीएमओ बाराबंकी इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं।



इलाज में गड़बड़ी का विरोध करने पर धमकी देने का आरोप

संगीता देवी ने अपनी शिकायत में इलाज को लेकर विरोध जताने पर उन्हें और उनके पति को धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया है। महिला के मुताबिक, जब उन्होंने उपचार में कथित गड़बड़ी और खर्च को लेकर सवाल उठाए, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा।

इस आरोप के सामने आने के बाद मामले में चिकित्सा संबंधी शिकायत के साथ-साथ कथित धमकी का पहलू भी जुड़ गया है। महिला ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, धमकी दिए जाने के आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस संबंध में पुलिस स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है। शिकायत में लगाए गए आरोपों और उनसे जुड़े तथ्यों की जांच के बाद ही इस पहलू पर स्थिति स्पष्ट होगी।

संगीता देवी के मुताबिक, जनवरी 2026 में पेट की बीमारी की वजह से उन्होंने आस्था हॉस्पिटल में इलाज कराया था। इसी दौरान उनका ऑपरेशन किया गया। महिला का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान उपचार में गड़बड़ी हुई, जिसके बाद भी उनकी परेशानी बनी रही। इस तरह मामले में शिकायतकर्ता और अस्पताल प्रबंधन के दावे अलग-अलग हैं। एक ओर महिला ने ऑपरेशन के दौरान कथित गड़बड़ी, इलाज पर अधिक खर्च और धमकी देने के आरोप लगाए हैं, वहीं अस्पताल संचालक ने इन आरोपों को खारिज किया है।

आत्मदाह की कोशिश के बाद डीएम ऑफिस में बढ़ी सुरक्षा

दो युवकों के प्रयास के बाद अब हर गतिविधि पर रहेगी सीसीटीवी की नजर

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव जिलाधिकारी कार्यालय की सुरक्षा शुक्रवार से व्यवस्था अब और सख्त कर दी गई है। कार्यालय के मुख्य गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के जरिए मेन रोड से लेकर कार्यालय के अंदर प्रवेश करने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। पहले मैनुअल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी, अब तकनीकी निगरानी का भी इंतजाम किया गया है। पिछले 10 दिनों में अलग-अलग मामलों में दो युवकों के ज्वलनशील पदार्थ लेकर आत्मदाह का प्रयास करने की घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह कदम अहम माना जा रहा है। डीएम कार्यालय में प्रतिदिन विभिन्न समस्याओं और



शिकायतों को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इनमें जमीन विवाद, राजस्व संबंधी मामले, सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतें और अन्य समस्याएं शामिल होती हैं। ऐसे में कार्यालय परिसर में आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मुख्य गेट पर कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों का दायरा मेन रोड की तरफ और कार्यालय के अंदर की ओर रखा गया है।प्रवेश करने वाले लोगों की गतिविधियां निगरानी में रहें। पिछले 10 दिनों में दो अलग-अलग मामलों में युवकों ने डीएम कार्यालय में ज्वलनशील पदार्थ लेकर आत्मदाह करने का प्रयास किया था। इन घटनाओं ने कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ाई। शिकायतों के निस्तारण की उम्मीद में अधिकारी से मिलने पहुंचने वाले लोगों के बीच ऐसी घटनाओं से परिसर में मौजूद कर्मचारियों और अन्य फरियादियों की सुरक्षा का सवाल भी खड़ा हुआ। इसी को देखते हुए कार्यालय के मुख्य गेट पर निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है। सीसीटीवी कैमरों से आने-जाने वालों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी।

सम्पादकीय

एक आवश्यक निर्णय



यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय से यह स्पष्ट कर दिया कि यदि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति मतांतरण कर लेता है तो फिर वह आरक्षण का लाभ पाने का अधिकारी नहीं रहेगा। हालांकि ऐसा ही निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने भी दिया था, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने उसे शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी, क्योंकि वह अपने उस नियम को बनाए रखना चाहती थी, जिसके तहत उसने यह सुविधा दी थी कि यदि एससी या ओबीसी समुदाय के लोग इस्लाम या ईसाई मत अपना लेते हैं तो भी आरक्षण के लाभ पाते रह सकते हैं। यह केवल सनातन परिवार के आरक्षित वर्गों के अधिकारों में कटौती करने वाला ही नहीं, बल्कि एक तरह से मतांतरण को बल देने वाला नियम था।

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एससी या ओबीसी वर्ग के अनेक हिंदू, सिख या बौद्ध अपना धर्म त्याग देते हैं और फिर यह मांग करने लगते हैं कि मतांतरण के बाद भी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए। ऐसी मांग का समर्थन कई मुस्लिम एवं ईसाई संगठन भी करते हैं। हालांकि ऐसा करके वे अपने इस दावे की पोल ही खोलते हैं कि उनके यहां न तो जाति है और न ही किसी तरह का जातिगत भेदभाव। ध्यान रहे इसी तरह के दावों के बहाने ही वे निर्धन एवं अशिक्षित हिंदुओं, सिखों आदि को मतांतरित होने का प्रलोभन देते हैं। कटु सच्चाई यह है कि एससी अथवा ओबीसी वर्ग के लोग मतांतरित होने के बाद भी अपने नए पंथ में जातिगत भेदभाव और वैमनस्य का शिकार होते हैं। इसी कारण दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों के संगठन बने हुए हैं।

निःसंदेह समस्या केवल इतनी ही नहीं थी कि तमिलनाडु सरकार ने जैसा नियम बना रखा था, उससे मतांतरण कराने वालों को प्रोत्साहन मिल रहा था और एससी एवं ओबीसी के अधिकारों में सेंधमारी भी हो रही थी, बल्कि यह भी थी कि हिंदू धर्म त्यागने वाले एससी या ओबीसी आरक्षण के साथ ही अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ भी पाने लगते थे। इस दोहरे लाभ का आकर्षण भी छल-छद्म और लोभ-लालच से मतांतरण कराने वालों के पक्ष में काम करता था और इसका सबसे अधिक नुकसान हिंदू समाज उठाता था, क्योंकि सिखों और बौद्धों को तो अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है।यह कोई छिपी बात नहीं कि हिंदू समाज खास तौर पर कपट और लालच से मतांतरण अभियानों में लिप्त ईसाई और मुस्लिम संगठनों के निशाने पर है। भले ही एक के बाद एक राज्य सरकारें छल-कपट से होने वाले मतांतरण को रोकने के कानून बना रही हों या उन्हें कठोर कर रही हों, लेकिन मतांतरण थम नहीं रहा है। इसका मूल कारण पंथ प्रचार की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। यह दुरुपयोग कैसे रुके, इस पर सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के आवश्यक न्यायिक फैसलों के उजाले



> सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्पष्ट किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है कि अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के व्यक्तियों द्वारा धर्मांतरण करने पर उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

लोकतंत्र की मजबूती का वास्तविक प्रमाण केवल चुनावों का नियमित आयोजन, संसद में बहुमत अथवा राजनीतिक दलों की लोकप्रियता नहीं है, बल्कि यह है कि संविधान के सामने सत्ता, विपक्ष और सामान्य नागरिक की स्थिति समान हो। जब सामाजिक न्याय, आरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता और चुनावी निष्पक्षता जैसे प्रश्न एक साथ राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आते हैं, तब सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। न्यायपालिका वह संवैधानिक संस्था है, जिससे नागरिक यह अपेक्षा करता है कि वह राजनीतिक आग्रहों, सामाजिक दबावों और सत्ता के प्रभाव से मुक्त रहकर न्याय का मार्ग प्रशस्त करेगी। आज आरक्षण की पात्रता और धर्मांतरण से जुड़े विवादों से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया तथा न्यायालय की गरिमा तक, अनेक प्रश्न इसी अपेक्षा की कसौटी बनकर सामने हैं। इन प्रश्नों पर विचार करते समय आवश्यक है कि हम न किसी राजनीतिक पक्ष के प्रचारक बनें, न किसी धार्मिक समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह रखें, बल्कि संविधान की भावना और न्याय के व्यापक उद्देश्य को केंद्र में रखें। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण भारतीय संविधान की उन ऐतिहासिक व्यवस्थाओं में है, जिनका उद्देश्य सदियों से चले आ रहे सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता और भेदभाव के दुष्परिणामों को दूर करना है। यह केवल रोजगार अथवा शिक्षा में कुछ अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं, बल्कि उस सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संवैधानिक हस्तक्षेप है, जिसने बड़ी आबादी को लंबे समय तक समान अवसरों से वंचित रखा। इसलिए आरक्षण और धर्मांतरण के संबंध में होने वाली बहस को भावनाओं, धार्मिक आग्रहों अथवा राजनीतिक आरोपों के बजाय संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर समझना चाहिए। तमिलनाडु सरकार द्वारा इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देना और अपने राज्य में इस प्रकार की सुविधा जारी रखना



कि इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी आरक्षण का लाभ मिलता रहे, वास्तव में सनातन संस्कृति के आरक्षित वर्गों के हितों को कमजोर करने वाला और धर्मांतरण को परोक्ष रूप से बढ़ावा देने वाला कदम था। यह विडंबना ही है कि एक तरफ कुछ संगठन यह दावा करते हैं कि उनके यहां जातिगत भेदभाव का अस्तित्व नहीं है, वहीं दूसरी ओर वे एससी और ओबीसी वर्ग के लोगों को अपने पंथ में आने के बाद भी आरक्षण का लाभ मिलने की पुरजोर वकालत करते हैं। इस प्रकार के दोहरे लाभ और प्रलोभनों के कारण न केवल धर्मांतरण की प्रवृत्ति को बल मिलता है, बल्कि हिंदू समाज को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि धर्मांतरित लोग आरक्षण के साथ-साथ अल्पसंख्यक दर्जे के लाभों का भी अनुचित दोहन करने लगते हैं। हालांकि विभिन्न राज्य सरकारें छल-कपट से होने वाले धर्मांतरण के विरुद्ध कड़े कानून बना रही हैं, फिर भी यह समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसका प्रमुख कारण धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर हो रहा इसका दुरुपयोग है। अब समय आ गया है कि इस गंभीर विषय पर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय मिलकर ठोस और प्रभावी कदम उठाएं ताकि इस दुरुपयोग को रोका जा सके।

इसी व्यापक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय का चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विवादों पर हस्तक्षेप भी उल्लेखनीय है। 12 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी सहित विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के नेताओं ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की ओर मार्च किया, इस पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया भी सराहनीय है। भले ही विपक्ष ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं, मतदाताओं के नाम हटाए जाने और निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए, इन आरोपों की सत्यता का निर्धारण न्यायिक परीक्षण और संबंधित अभिलेखों के आधार पर होना चाहिए, लोकतंत्र में चुनाव केवल सरकार चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक को अपनी राजनीतिक इच्छा व्यक्त करने का संवैधानिक अवसर है। इसलिए मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता किसी एक दल का नहीं, पूरे लोकतंत्र का प्रश्न है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करना एक गलत परम्परा का सूत्रपात है। 15 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने विपक्षी नेताओं की याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से जवाब माँगा। इससे स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग जैसी महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संस्था के निर्णय भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकते हैं। आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि उसके प्रत्येक निर्णय को प्रश्नों से परे मान लिया जाए। इसी प्रकार, किसी निर्णय से असहमति अपने आप में यह प्रमाणित नहीं करती कि आयोग ने अनुचित कार्य किया है। न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य आरोपों और तथ्यों के बीच अंतर स्पष्ट करना, निर्णय प्रक्रिया की वैधानिकता जाँचना तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसी घटनाक्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर के मार्च को लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य संबंधित नेताओं से भी जवाब माँगा। न्यायालय की चिंता यह थी कि राजनीतिक प्रदर्शन के माध्यम से न्यायपालिका पर दबाव बनाने की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस प्रसंग का मूल्यांकन करते समय यह समझना आवश्यक है कि शांतिपूर्ण विरोध, राजनीतिक असहमति और न्यायालय की गरिमा-तीनों लोकतंत्र के महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं। विपक्ष को सरकार और निर्वाचन आयोग से प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन न्यायिक संस्थाओं की स्वतंत्रता का सम्मान करना भी उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है।

- ललित गर्ग

विदेशी फंडिंग का आरोप : सनसनी से नहीं, सबूतों से तय होनी चाहिए सच्चाई

बिना प्रमाण गंभीर आरोप लगाना लोकतंत्र, राजनीतिक विमर्श और सार्वजनिक विश्वसनीयता के लिए कितना उचित है? यह सवाल अपने आप में ही प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। दुनिया के अनेक देशों में राजनीतिक गतिविधियों, चुनावी प्रक्रियाओं और जन आंदोलनों पर बाहरी प्रभाव को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं लेकिन किसी आशंका को प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना और किसी राजनीतिक दल पर विदेशी धन लेकर देश में अशांति फैलाने का आरोप लगाना दो अलग-अलग बातें हैं। यही अंतर जिम्मेदार पत्रकारिता, निष्पक्ष राजनीतिक विमर्श और लोकतांत्रिक मूल्यों की बुनियाद है। हाल ही में अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री मैरी मिलबेन के नाम से सोशल मीडिया के जरिये सामने आए एक बयान में भारत में सक्रिय एक राजनीतिक दल को अमेरिका से भारी वित्तीय सहायता मिलने का आरोप लगाया गया है। इस दावे में यह भी कहा गया है कि विदेशी धन का इस्तेमाल भारत की आंतरिक शांति को प्रभावित करने, सामाजिक विद्वेष बढ़ाने और केंद्र सरकार के कामकाज में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। आरोपों के समर्थन में कुछ व्यक्तियों और कथित वित्तीय समूहों का भी उल्लेख किया गया है। ऐसे गंभीर आरोप सामने आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि इन दावों के समर्थन में ठोस सबूत क्या हैं? क्या किसी बैंक खाते का विवरण सामने आया है? क्या किसी वित्तीय लेन-देन का दस्तावेज उपलब्ध है? क्या संबंधित एजेंसी ने कोई जांच की है? क्या किसी विश्वसनीय जांच रिपोर्ट या आधिकारिक दस्तावेज में इन आरोपों की पुष्टि हुई है? यदि इन सवालों के जवाब उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसे बयानों को प्रमाणित समाचार की तरह प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। किसी राजनीतिक दल को विदेशी धन मिलने का आरोप सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। यह एक गंभीर आरोप है, जिसका संबंध देश की संप्रभुता, राजनीतिक पारदर्शिता और कानून के पालन से जुड़ा है। यदि किसी दल या संगठन को अवैध विदेशी वित्तपोषण प्राप्त हुआ है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

- सौरभ वाष्णेय

विपक्ष का मुख्य...

अशोक भाटिया

न्याय की चौखट पर सियासत और संवैधानिक मर्यादा का संकट

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 12 अक्टूबर 2026 की तारीख एक ऐसी असाधारण और चिंताजनक घटना के रूप में दर्ज हो चुकी है, जिसने संवैधानिक संस्थाओं के बीच पारस्परिक सम्मान की सीमाओं को पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे 'स्पेशल इनटेंसिव रिवीजन' की प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट परिसर तक निकाला गया विरोध मार्च सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वह न्याय की सर्वोच्च देहरी पर जन-दबाव बनाने का एक ऐसा अभूतपूर्व प्रयास था, जिसकी अनुमति हमारा संवैधानिक ढांचा कभी नहीं देता। 15 अक्टूबर 2026 को इस संवेदनशील मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने जो बेहद सख्त रुख अपनाया, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र की आत्मा उसकी संस्थाओं की गरिमा और उनकी स्वतंत्रता में बसती है, न कि सड़कों पर उमड़ने वाली राजनीतिक भीड़ के कोलाहल में। अदालत का सुनवाई के दौरान यह कहना कि ₹हम आइवरी टावर (हाथीदांत के मीनारों) में नहीं बैठे हैं, हमें सब पता है कि बाहर क्या बयान दिए जा रहे हैं और कोर्ट के भीतर क्या कहा जा रहा है₹, देश के पूरे राजनीतिक नेतृत्व के लिए एक गंभीर और ऐतिहासिक चेतावनी है। जब देश का विपक्ष का नेता, जिसके पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है और जो संसद के भीतर देश की जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, स्वयं समर्थकों की भारी भीड़, नारेबाजी और हंगामे के बीच देश की सर्वोच्च अदालत की रजिस्ट्री में याचिका दाखिल करने पहुंचता है, तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या अब न्यायिक प्रक्रियाओं का फैसला भी सड़कों के संख्याबल से तय होगा? यह संपादकीय इसी गहरे और गंभीर संवैधानिक संकट का निष्पक्ष विश्लेषण करने का प्रयास है कि आखिर विपक्ष के इस कदम के पीछे की राजनीति क्या है, न्यायपालिका की चिंताएं कितनी जायज हैं और भारतीय लोकतंत्र को इस अभूतपूर्व संस्थागत टकराव से बचाने के लिए किस तरह के संतुलन की आवश्यकता है। इस पूरे विवाद की जड़ें किसी न्यायिक फैसले या अदालती आदेश में नहीं, बल्कि देश की चुनावी प्रक्रिया की शुचिता से जुड़ी हैं। चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में शुरू की गई 'स्पेशल इनटेंसिव रिवीजन' की कवायद को लेकर गठबंधन और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का मुख्य आरोप है कि इस विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के नाम पर देश भर में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। विपक्ष इसे 'वोटों की चोरी' और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की एक सोची-समझी राजनीतिक साजिश करार दे रहा है। इसी के विरोध में पिछले सप्ताह दिल्ली की सड़कों पर विपक्षी कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए थे, जहां पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज ने आग में घी का काम किया था। राजनीतिक रूप से चुनाव आयोग के फैसलों का विरोध करना और उस पर सवाल उठाना विपक्ष का न सिर्फ लोकतांत्रिक अधिकार है, बल्कि उसका कर्तव्य भी है। भारतीय चुनावी राजनीति में ईवीएम से लेकर मतदाता सूचियों में विसंगतियों के दावों तक, विपक्ष हमेशा से मुखर रहा है। इसी सिलसिले में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव सहित 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने एक संयुक्त रिट याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया, तो देश को लगा कि यह लड़ाई अब पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक दायरे में लड़ी जाएगी। लेकिन, कानूनी याचिका दायर करने की सामान्य प्रक्रिया को जिस तरह से एक विशाल 'राजनीतिक जुलूस' में तब्दील कर दिया गया, उसने इस कानूनी लड़ाई के वास्तविक उद्देश्य पर ही बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए। 12 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के लुटियंस जोन में जो दृश्य दिखाई दिए, वे देश के न्यायिक इतिहास में बेहद दुर्लभ और विचलित करने वाले थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, विपक्षी दलों के सांसद, छात्र संगठन और समर्थक संसद मार्ग से होते हुए सुप्रीम कोर्ट परिसर की ओर बढ़े। हालांकि सुरक्षा कारणों से पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी नेताओं का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल और समर्थकों की एक अनियंत्रित भीड़ सुप्रीम कोर्ट के भीतर स्थित 'फाइलिंग काउंटर' तक पहुंच गई।एक ऐसे समय में जब कोर्ट की रजिस्ट्री अपने दैनिक कार्य को समेट रही थी, परिसर के भीतर अचानक पैदा हुए इस राजनीतिक कोलाहल, नारेबाजी और समर्थकों के हुजूम ने सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक तंत्र को कुछ समय के लिए ठप कर दिया।

इससे न्यायालयों...

डॉ0 सीमा गुप्ता

अमेठी में अत्याधुनिक साइबर क्राइम थाने से डिजिटल सुरक्षा तंत्र होगा सुदृढ़

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और डिजिटल अपराधों की जांच को अत्याधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों से सुदृढ़ करने के संकल्प के तहत सुरक्षा ढांचे का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में अमेठी जनपद में डिजिटल एवं साइबर अपराधों की रोकथाम, त्वरित विवेचना तथा तकनीकी साक्ष्य संकलन को आधुनिक मजबूती देने के उद्देश्य से उच्च तकनीकी सुविधाओं से युक्त साइबर क्राइम थाने के प्रशासनिक भवन का निर्माण तीव्र गति से कराया जा रहा है। जनपद के गौरीगंज क्षेत्र अंतर्गत सैंठा रोड स्थित बाहापुर ग्राम पंचायत में 0.285 हेक्टेयर भूमि पर इस विशिष्ट प्रशासनिक भवन की स्थापना की जा रही है। गृह एवं गोपनीय विभाग द्वारा वित्तपोषित इस महत्वपूर्ण परियोजना की कुल लागत 3.69 करोड़ रुपये है। कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की निर्माण इकाई द्वारा भवन का निर्माण गुणवत्तापूर्ण मानकों के अनुरूप सुनिश्चित कराया जा रहा है। जिला प्रशासन की सतत निगरानी में परियोजना का 90 प्रतिशत से अधिक भौतिक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्यों को भी समयबद्ध रूप से पूरा किया जा रहा है, जिससे आगामी पर्व दीपावली तक यह आधुनिक परिसर पूरी तरह तैयार होकर क्रियाशील होने की दिशा में अग्रसर है। इस भवन के क्रियान्वयन के उपरांत अमेठी में साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों, तकनीकी परीक्षण, डिजिटल साक्ष्यों की विवेचना और कानूनी प्रक्रियाओं के निष्पादन हेतु एक ही छत के नीचे आधुनिक अवसंरचना उपलब्ध हो सकेगी। भविष्य की साइबर सुरक्षा चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए इस भवन का वास्तु एवं तकनीकी प्रारूप विशेष रूप से तैयार किया गया है। भवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक अत्याधुनिक 'साइबर लैब एवं डिजिटल फोरेंसिक कक्ष' है। यहां कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क और सिम कार्ड जैसे डिजिटल उपकरणों का वैज्ञानिक व तकनीकी परीक्षण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, डिलीट किए गए डेटा की सुरक्षित रिकवरी, इंटरनेट प्रोटोकॉल विश्लेषण और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े जटिल मामलों की त्वरित जांच संभव होगी। साइबर अपराधों की सफल कानूनी विवेचना में साक्ष्यों की सत्यता एवं उनकी सुरक्षा अत्यंत संवेदनशील विषय होती है। नए भवन में स्थापित होने वाली प्रयोगशाला से विवेचकों और तकनीकी विशेषज्ञों को साक्ष्यों की वैज्ञानिक प्रामाणिकता (चेन ऑफ कस्टडी) बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उपकरण सुलभ होंगे। इससे न्यायालयों में मामलों के सफल अभियोजन और अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने में सहायता मिलेगी। आम नागरिकों और पीड़ितों की त्वरित सुनवाई हेतु भवन परिसर में एक समर्पित 'शिकायत एवं सहायता कक्ष' स्थापित किया जा रहा है। यह सहायता केंद्र केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल तथा राष्ट्रीय वित्तीय धोखाधड़ी हेल्पलाइन नंबर श्1930श् के साथ रियल-टाइम समन्वय में कार्य करेगा। किसी भी ऑनलाइन ठगी की स्थिति में त्वरित सूचना दर्ज कर संबंधित बैंकों, वित्तीय संस्थानों और पेमेंट गेटवे से संपर्क स्थापित कर धन की निकासी पर तत्काल रोक लगवाने में यह व्यवस्था अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

जरा हटके

श्रीमती ममता के...

बी0एल0 यादव

समूह की महिला सदस्य ने मिट्टी के कुल्हड़ों से गढ़ी आत्मनिर्भरता की कहानी

उत्तर प्रदेश के झाँसी जनपद के चिरगाँव विकासखंड के ग्राम उज्ज्यान की रहने वाली 30 वर्षीय श्रीमती ममता प्रजापति आज ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायी मिसाल बन चुकी हैं। कभी परिवार की सीमित आय से घर चलाने में सहयोग देने की चिंता करने वाली ममता ने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर न केवल अपने लिए रोजगार का अवसर तैयार किया, बल्कि पारंपरिक मिट्टी के कुल्हड़ों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर अपना उद्यम खड़ा किया। आज उनकी मिट्टी के कुल्हड़ बनाने की इकाई से उन्हें औसतन रू 16,000 प्रतिमाह तथा लगभग रू0 2 लाख वार्षिक आय प्राप्त हो रही है।

श्रीमती ममता ने 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है। विवाह के बाद उनका अधिकांश समय घर-परिवार की जिम्मेदारियों में बीतता था। उनके पति दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। सीमित आय और बढ़ते घरेलू खर्चों के बीच ममता ने महसूस किया कि यदि वह स्वयं भी कोई रोजगार शुरू करें, तो परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। इसी सोच ने उन्हें आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

श्रीमती ममता के जीवन में बदलाव की शुरुआत 'अमृत माटी स्वयं सहायता समूह' से जुड़ने के साथ शुरू हुई। समूह की बैठकों में नियमित सहभागिता ने उनमें बचत, अनुशासन, सामूहिक प्रयास और आर्थिक



प्रबंधन की समझ विकसित की। स्वयं सहायता समूह से मिली प्रेरणा और सहयोग ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्हें अपना उद्यम शुरू करने का साहस दिया। स्वयं सहायता समूह के सहयोग से ऋण प्राप्त कर ममता ने मिट्टी के कुल्हड़ बनाने की इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने पारंपरिक कला को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए मशीन के माध्यम से मिट्टी के कुल्हड़ एवं मिट्टी के कप तैयार करने का कार्य शुरू किया। मशीन के उपयोग से उत्पादन क्षमता बढ़ी और शारीरिक श्रम भी कम हुआ। धीरे-धीरे उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया को समझा, उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान दिया और स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप अपने कार्य को आगे बढ़ाया। उद्यम की शुरुआत आसान नहीं थी। ममता के सामने कच्चे माल की व्यवस्था, बाजार की जरूरतों को समझने, उत्पादों को ग्राहकों तक पहुँचाने और व्यवसाय का हिसाब-किताब रखने जैसी कई चुनौतियाँ थीं। लेकिन उन्होंने चुनौतियों को बाधा नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में लिया। निरंतर प्रयास और सीखने की इच्छा के साथ उन्होंने अपने व्यवसाय को धीरे-धीरे मजबूत बना लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें व्यवसाय की योजना बनाने, उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर करने, लागत प्रबंधन, बाजार की संभावनाओं को समझने और मार्केट लिंकेज विकसित करने की जानकारी मिली। उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने के साथ-साथ व्यवसाय के व्यवस्थित संचालन के लिए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बैनर सपोर्ट और बही-खाता रखने के लिए रजिस्टर उपलब्ध होने से भी उनके उद्यम को व्यवस्थित रूप देने में मदद मिली। आज ममता अपने गाँव में रहकर ही आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। उनकी इकाई में तैयार किए गए मिट्टी के कुल्हड़ स्थानीय बाजार और आसपास के क्षेत्रों में उपयोग किए जा रहे हैं। पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के प्रति बढ़ती जागरूकता के बीच मिट्टी के कुल्हड़ों की मांग उनके व्यवसाय के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। श्रीमती ममता की सफलता का सबसे बड़ा पहलू यह है कि उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने दिया। स्वयं सहायता समूह से मिले सहयोग, प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने घर की जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपना व्यवसाय खड़ा किया। आज वह परिवार की आर्थिक जरूरतों में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं और अपने हुनर के माध्यम से अपनी अलग पहचान बना रही हैं। ममता का सपना अब अपने उद्यम को और अधिक विस्तार देने का है। वह उत्पादन बढ़ाना, बाजार से बेहतर जुड़ाव स्थापित करना और भविष्य में अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करना चाहती हैं। उनका मानना है कि प्रदेश सरकार के सहयोग से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं के माध्यम से यदि सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और अवसर मिलें, तो महिलायें अपने घर और गाँव में रहते हुए भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियां, योजनाएं आज धरातल पर उतर रही है। श्रीमती ममता प्रजापति की कहानी इस बात का उदाहरण है कि स्वयं सहायता समूह केवल बचत और ऋण का माध्यम नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास, कौशल और उद्यमशीलता को नई दिशा देने का सशक्त मंच है। मिट्टी को आकार देकर कुल्हड़ बनाने वाली ममता ने उसी मिट्टी से अपने सपनों को भी आकार दिया है। आज उनका उद्यम उनके परिवार की आय बढ़ाने के साथ-साथ आत्मनिर्भर ग्रामीण महिला की नई पहचान गढ़ रहा है।

पिता-पुत्र और पोती समेत 5 की मौत

100 की स्पीड में कार पेड़ से टकराई, 3 की हालत गंभीर

घटना

तमसा संकेत एजेंसी

बुलंदशहर। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ईको कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 5 की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कार में 8 लोग सवार थे।

सभी कासगंज से बेलोन माता मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे।

हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया। उसमें सवार लोग अंदर फंस गए।

मौके पर चीख-पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार की रफ्तार 100 किमी प्रति घंटे से ज्यादा थी। सूचना पर पुलिस मौके



पर पहुंची। घायलों को कार से बाहर निकाला गया। सभी को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया।

वहां से 3 घायलों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हादसे में रामदीन (50), उनके बेटे लोकेन्द्र (26), एक साल की पोती प्रगति, बड़ी बहू बबिता (36) और कार चालक शिवशेखर मिश्रा (55) की मौत हो गई। हादसा जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर डिबाई तहसील के नरौरा थाना क्षेत्र में है। हादसे में घायल ललिता ने बताया- उनके पति लोकेन्द्र डिलीवरी एजेंट का काम करते हैं।

कासगंज से बेलोन माता के दर्शन करने जा रहे थे

रामदीन राजपूत (50) कासगंज के थाना सिडपुरा क्षेत्र के दहेली बुजुर्ग गांव के रहने वाले थे। उनके तीन बेटे हैं। बड़े बेटे प्रवीण और संजय दिल्ली में रहते हैं। छोटा बेटा लोकेन्द्र उर्फ टिंकू (26) गांव में रहता है। रामदीन की तीन बेटियां भी हैं। इनमें से दो की शादी हो चुकी है। शुक्रवार सुबह रामदीन परिवार के साथ बुलंदशहर के नरौरा के पास बेलोन गांव स्थित सर्वमंगला माता (बेलोन माता) के दर्शन करने जा रहे थे। कार में उनके लोकेन्द्र, बहू ललिता (20), बड़ी बहू बबिता, पोता प्रतीक और पोतियां अनिका (11) प्रगति (1) थीं।





66 प्रभारी डीएम निशा ग्रेवाल ने बताया- शुरुआती जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को नींद का झपका आने से कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 8 लोग घायल हुए थे। सभी को डिबाई सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। बाकी 3 घायलों को बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

'पदक लाओ, पद पाओ' के तहत खिलाड़ियों की सीधी भर्ती : मुख्यमंत्री

नारीशक्ति के अदम्य साहस, अटूट संकल्प और अजेय पराक्रम का प्रतीक हैं मां कात्यायनी : मुख्यमंत्री

तमसा संकेत संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की षष्ठी तिथि की बधाई दी। उन्होंने कहा कि समस्त बाधाओं और आसुरी प्रवृत्तियों का संहार करने वाली मां कात्यायनी नारीशक्ति के अदम्य साहस, अटूट संकल्प और अजेय पराक्रम का प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री ने आस्था, विकास व विरासत के जरिए राज्य में आए बदलाव से अवगत कराते हुए कहा कि प्रदेश में अब 'पदक लाओ, पद पाओ' के तहत खिलाड़ियों की सीधी भर्ती हो रही है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट कर पिछली सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधा। कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में भय और अराजकता का ऐसा माहौल था, जहां बेटियों के सपनों पर पहरे थे, हौसलों पर बंदिशें थीं और प्रतिभा अवसर के अभाव में दम तोड़ने को मजबूर थी। खेल के मैदान माफिया के कब्जे में थे, संसाधन नदारद थे और बेटियों की उड़ान को पंख देने के बजाय, उनके सपनों को चारदीवारी में कैद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने 2017 के बाद आए बदलाव को भी इंगित किया। कहा कि विगत साढ़े 9 वर्षों में प्रदेश में बदलाव की नई गाथा लिखी गई है। भय का स्थान सुरक्षा ने लिया है, उपेक्षा का स्थान प्रोत्साहन ने लिया है और संसाधनों के अभाव का स्थान खेल सुविधाओं के विस्तार ने लिया है। गांव के खेल मैदानों और ब्लॉक स्तरीय मिनी स्टेडियम से लेकर जिला स्तरीय स्टेडियम, मंडल स्तरीय स्पोर्ट्स कॉलेज तथा मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तक, बेटियों को अपनी प्रतिभा निखारने का सशक्त आधार मिल रहा है। प्रतिभा को प्रोत्साहन, उपलब्धियों को सम्मान और भविष्य को सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने बताया कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ एवं एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को लाखों-करोड़ों के पुरस्कार और 'पदक लाओ, पद पाओ' के तहत सीधी भर्ती जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहन, उपलब्धियों को सम्मान और भविष्य को सुरक्षा प्रदान कर रही है। इस परिवर्तन की गूंज अंतरराष्ट्रीय खेल मंचों पर भी सुनाई दे रही है। एथलेटिक्स में पारुल चौधरी, प्रियंका गोस्वामी, प्राची चौधरी और अन्नू रानी, जूडो में अस्मिता डे, क्रिकेट में दीप्ति शर्मा और मेघना सिंह, हॉकी में वंदना कटारिया, कुश्ती में दिव्या काकरान ने कॉमनवेल्थ एवं एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।

फास्ट न्यूज

वोटर लिस्ट में नाम छूटा तो आज मिलेगा मौका

अम्बेडकरनगर। मतदाता सूची में अब तक नाम दर्ज नहीं करा सके पात्र नागरिकों और पहली बार मतदान का अधिकार पाने वाले युवाओं के लिए शनिवार को विशेष अवसर मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 17 अक्टूबर को जनपद के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष मतदाता पंजीकरण कैम्प आयोजित किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे।

महिला पंचायत सहायक की गला दबाकर हत्या

सहारनपुर। सहारनपुर में 27 साल की महिला पंचायत सहायक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। लाश कमरे में चारपाई पर मिली। शुक्रवार सुबह जब भाई जगाने पहुंचा तो बहन कोमल को बेहोशी की हालत में पाया। पानी के छींटे मारने के बाद भी नहीं उठी तो भागकर पुलिस के पास गया। कहा कि घर पर बहन की हत्या हो गई है। पुलिस, फॉरेंसिक टीमों के साथ मौके पर पहुंची। सबूत जुटाकर लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पता चला कि रात में घर पर कोमल और उसका भाई ही था।

मथुरा पुलिस ने पांच बिछड़े दंपती को मिलाया

मथुरा। मथुरा में पति-पत्नी के बीच बढ़ते मनमुटाव और पारिवारिक विवादों के कारण टूटने की कगार पर पहुंचे रिश्तों को बचाने के लिए मथुरा पुलिस की मिशन शक्ति टीम ने शुक्रवार को सराहनीय पहल की है। सीओ सिटी आईपीएस आशना चौधरी के निर्देशन में महिला थाना पुलिस ने काउंसलिंग के माध्यम से पांच दंपतियों के बीच चल रहे विवादों को सुलझाकर उन्हें फिर से एक साथ रहने के लिए राजी किया।

दुर्गा पूजा से पहले टांडा में दुरुस्त हुई सड़क, श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत

एसडीएम राहुल गुप्ता के पर्यवेक्षण में जल निगम नगरीय ने असमतल हिस्सों को कराया ठीक

तमसा संकेत संवाददाता

अम्बेडकरनगर।दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए टांडा में असमतल सड़क को दुरुस्त कराया गया। जल निगम नगरीय द्वारा पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क पुनर्स्थापन किए जाने के बावजूद कुछ हिस्से उभरे हुए और असमतल रह गए थे। इससे आवागमन में परेशानी की आशंका थी। उपजिलाधिकारी राहुल गुप्ता के पर्यवेक्षण में अधिशासी अभियंता, जल निगम नगरीय के निर्देशन में जल जीवन अर्बन टीम ने सड़क के उभरे हुए एवं असमतल हिस्सों को ठीक कराया। इस त्वरित कार्रवाई से



दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि त्योहार के दृष्टिगत जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मोदी-योगी ने मिलकर ज्ञानेश कुमार से 13 लाख फ़र्जी वोट जुड़वा दिए, 85 हजार वोट बिना कारण कटवाए: संजय सिंह

यूपी चुनाव में वोट चोरी का काम सीनाजोरी से जारी है: संजय सिंह

- 13 लाख नाम किसके जोड़े गए, चुनाव आयोग पूरी सूची सार्वजनिक करे: संजय सिंह
- स्वनिर्मित फॉर्म-7 कैसे बना, समयसीमा खत्म होने के बाद नाम काटने के 1,10,476 आवेदन कैसे आये? चुनाव है या मजाक: संजय सिंह

तमसा संकेत संवाददाता

लखनऊ। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में कथित अनियमिताओं को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली और बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी वोट चोरी का खेल शुरू हो गया है। चुनाव आयोग के अनुसार, SIR से पहले प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे और पुनरीक्षण में लगभग 2 करोड़ 90 लाख नाम काटे जाने की बात सामने आई। इसके बाद नाम जोड़ने के लिए 84 लाख और नाम काटने के लिए 4 लाख 30 हजार आवेदन आने की जानकारी दी गई।



66 संजय सिंह ने गोंडा जिले की तरबगंज विधानसभा का उदाहरण देते हुए कहा कि रेशमा नाम की महिला के नाम से 188 मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन दिए गए, लेकिन उसके बारे में जानकारी जुटाने पर उसका पता नहीं चल सका।

85 हजार नाम बिना कारण काटे जाने का आरोप, फॉर्म-7 पर उठाए सवाल: संजय सिंह

संजय सिंह ने कहा कि फॉर्म-6 के तहत नाम जोड़ने के आवेदन की BLO जांच करता है और ERO नाम जोड़ने का फैसला लेता है। इसी तरह फॉर्म-7 के तहत नाम हटाने के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया और कारण जरूरी हैं।

13 लाख नाम किसके जोड़े गए, चुनाव आयोग पूरी सूची सार्वजनिक करे: संजय सिंह

संजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक फॉर्म-6 के तहत जोड़े गए नामों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि राजनीतिक दल बूथ और विधानसभा स्तर पर जांच कर सकें।

उन्होंने सवाल उठाया कि 84 लाख आवेदनों के बीच सार्वजनिक जानकारी में 71 लाख 13 हजार नाम जोड़े जाने का उल्लेख है, तो बाकी 13 लाख नाम किसके हैं और कहां जोड़े गए? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ज्ञानेश कुमार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 13 लाख फर्जी वोट जुड़वाए हैं। नाम से बड़ी संख्या में नाम काटने के आवेदन दिए गए और उनमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक बताई गई। उन्होंने कहा कि 130 विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 हजार या 260 विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 हजार नाम बढ़ने से चुनाव का परिणाम बदल सकता है।

चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि ये नाम किसके कहने पर और किन बूथों पर जोड़े गए। क्या यह सूची नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या पंकज चौधरी ने दी थी? आयोग इस बारे में जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा जय सिंह ने कई मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से बड़ी संख्या में नाम काटने के आवेदन दिए गए और उनमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक बताई गई।

ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार 62 वर्षीय महिला की मौत, चालक फरार

ओमैक्स तिराहे के पास हुआ हादसा, अस्पताल में उपचार के दौरान तोड़ा दम

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। बिजनौर थाना क्षेत्र के औरंगाबाद चौकी अंतर्गत ओमैक्स तिराहे के पास शुक्रवार सुबह ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार 62 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के दौरान अस्पताल में महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार 16 अक्टूबर को सुबह करीब 10:30 बजे थाना पुलिस को ओमैक्स तिराहे के पास सड़क दुर्घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि एक अज्ञात ट्रैक्टर चालक ने स्कूटी संख्या UP32LR4047 में टक्कर मार दी थी। हादसे में स्कूटी सवार रीना देवी (62), पत्नी राजेश कुमार, निवासी कटरा मोहल्ला, थाना बिजनौर,



लखनऊ गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए विनायक मेडिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उनकी मृत्यु की सूचना दी। इसके बाद महिला उपनिरीक्षक द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस दुर्घटना में शामिल अज्ञात ट्रैक्टर और उसके चालक की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल पर शांति व्यवस्था कायम है।

प्रभारी मंत्री ने फैजुल्लागंज में जलभराव की स्थिति का लिया जायजा

बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने में न हो कोई कोताही : सुरेश कुमार खन्ना

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने फैजुल्लागंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जलनिकासी में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों तक आवश्यक सुविधाएं निर्बाध रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए। कहा कि आपदा की इस घड़ी में नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें त्वरित राहत उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रभारी मंत्री ने अतिवृष्टि से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पिछले 16 दिनों से लगातार मोर्चा संभाले महापौर, नगर आयुक्त एवं नगर निगम की टीम



तथा जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशासन की सक्रियता से जलभराव, सड़क एवं पेयजल संबंधी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा रहा है। श्री खन्ना ने प्रभावित परिवारों के लिए स्वच्छ पेयजल एवं राशन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष सफाई अभियान, कीटनाशक छिड़काव एवं फॉगिंग पर जोर दिया। उन्होंने राहत कार्यों में सीएसआर के माध्यम से सहयोग कर रहे संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं की भी सराहना की। प्रभारी मंत्री ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों से पूरी तरह पानी निकलने में लगभग तीन से चार दिन लगने का अनुमान है। इसके बाद भी अगले 10 से 12 दिनों तक राहत, स्वच्छता एवं पुनर्वास अभियान जारी रहेगा, ताकि जनजीवन शीघ्र सामान्य हो सके। श्री खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने





प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर राहत एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं, जबकि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी मौके पर पहुंचकर नागरिकों का हाल जाना है और राहत का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार संकट की इस घड़ी में बाढ़ प्रभावितों के साथ मजबूती से खड़ी है। स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक शासन-प्रशासन राहत एवं पुनर्वास कार्यों में कोई कमी नहीं आने देगा।

सम्मान : प्रदेश के सभी प्रमुख देवी मंदिरों में होंगे सांस्कृतिक आयोजन, महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन पर जोर

योगी सरकार सप्तमी से नवमी तक मंदिरों में कराएगी देवी गीत व दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में शक्ति आराधना के साथ आज से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का संदेश गूंजेगा। मिशन शक्ति के तहत योगी सरकार शारदीय नवरात्र की सप्तमी से नवमी तिथि (शनिवार से सोमवार) तक चयनित मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराएगी। इनमें पारंपरिक देवी गीतों पर आधारित गायन और दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। नवरात्र की सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर होने वाले कार्यक्रमों में देवी गीतों की पारंपरिक गायन शैली को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होगा। इन आयोजनों के जरिए शक्ति आराधना



की परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया जाएगा।

हमारा प्रयास है कि धार्मिक आयोजन सामाजिक बदलाव का माध्यम बनें और महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करें। इन कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय कलाकारों, विशेषकर महिला कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

योगी सरकार इन मंदिरों में कराएगी त्रिदिवसीय आयोजन

- मां विंध्यवासिनी देवी- मीरजापुर
- विशालाक्षी मंदिर- वाराणसी
- ज्वाला देवी-सोनभद्र
- सीता समाहित स्थल- सीतामढ़ी (भदोही)
- अलोपशंकरी देवी-प्रयागराज
- ललिता देवी- प्रयागराज
- कड़ावासिनी- कौशांबी
- देवीपाटन- बलरामपुर
- ललिता देवी- नैमिषारण्य (सीतापुर)
- शाकुंभरी देवी- सहारनपुर
- कात्यायनी देवी- मथुरा
- मां शीतला चौकिया धाम- जौनपुर
- बेल्हा देवी- प्रतापगढ़
- महालक्ष्मी देवी मंदिर- वाराणसी
- चंद्रिका देवी- उन्नाव
- देवकाली मंदिर- औरैया
- मां तरकुलहा देवी धाम- गोरखपुर
- मां शीतला माता स्थल-मऊ
- मां सिंह वाहिनी काली देवी- चित्रकूट
- गायत्री शक्तिपीठ- हमीरपुर
- बैरागढ़ माता- कोंच जालौन
- कुष्मांडा देवी-घाटमपुर
- शीतला माता मंदिर- मैनपुरी
- चामुंडा देवी मंदिर- फिरोजाबाद
- चंद्रिका देवी मंदिर-लखनऊ
- संकटा देवी मंदिर- लखनऊ।

स्थानीय कलाकारों को मंच देगी योगी सरकार

प्रत्येक मंदिर में तीन स्थानीय कलाकार प्रस्तुति देंगे। इस तरह कुल 78 कलाकारों को अपनी कला दिखाने का अवसर मिलेगा। इनमें महिला कलाकारों की संख्या अधिक रहेगी। लखनऊ के चंद्रिका देवी, संकटा देवी मंदिर, प्रयागराज के अलोपी देवी और ललिता देवी मंदिर में तीन-तीन स्थानीय कलाकार प्रस्तुति देंगे। इस तरह लखनऊ और प्रयागराज के चार मंदिरों में कुल 12 कलाकारों को अवसर मिलेगा। बाकी 22 मंदिरों में तीन-तीन कलाकार कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि शारदीय नवरात्र आस्था, शक्ति और सांस्कृतिक परंपराओं का पर्व है। हमारा प्रयास है कि धार्मिक आयोजन सामाजिक बदलाव का माध्यम बनें और महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करें। इन कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय कलाकारों, विशेषकर महिला कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त बजट दे योगी सरकार: डॉ. राजेश्वर सिंह

- तीन माह तक विशेष निगरानी अभियान चलाने और टास्क फोर्स गठित करने की मुख्यमंत्री से मांग, विभागों की जवाबदेही तय करने पर दिया जोर।

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। सरोजनीनगर के विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने, विशेष टास्क फोर्स गठित करने और अगले तीन माह तक सघन निगरानी अभियान चलाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के साथ आम नागरिकों की स्थानीय समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।



डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने आधारभूत संरचना, निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, मेट्रो, एक्सप्रेसवे और अन्य बड़ी परियोजनाओं के विस्तार से प्रदेश में निवेश, उद्योग तथा रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की। विधायक ने कहा कि भारी बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इससे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सड़क मरम्मत के कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने की जरूरत है। उन्होंने जोर दिया कि केवल समस्याओं को सामने लाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी समाधान तय समय-सीमा में होना चाहिए। डॉ. सिंह ने सुझाव दिया कि लोक निर्माण विभाग, नगर निगमों, नगर निकायों, जिला पंचायतों, विकास प्राधिकरणों और अन्य संबंधित विभागों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाए। प्रत्येक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची तैयार कर मरम्मत की समय-सीमा तय की जाए और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसके साथ ही निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी, गुणवत्ता की जांच तथा नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

रैली स्थल पर भरा पानी, सुबह से हो रही बारिश, एमएलसी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा थी

सीएम योगी का आगरा दौरा रद्द...

परेशानी

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। आगरा में लगातार हो रही बारिश के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया। शुक्रवार सुबह से हो रही बारिश के चलते फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड में पानी भर गया और पूरे मैदान में कीचड़ हो गई। इससे जनसभा के आयोजन में परेशानी पैदा हो गई। मौसम की स्थिति और जनसभा स्थल की खराब हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री के करीब तीन घंटे के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की ओर से व्यापक तैयारियां की गई थीं। कार्यक्रम में भाजपा के स्नातक और शिक्षक एमएलसी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा प्रस्तावित थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को ताजमहल के पूर्वी गेट के पास निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम का निरीक्षण भी करना था। बारिश के कारण दोनों प्रमुख कार्यक्रम नहीं हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड में प्रस्तावित थी। इस सभा के माध्यम से भाजपा स्नातक और शिक्षक एमएलसी प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने की तैयारी थी। कार्यक्रम में आगरा के साथ आसपास के जिलों से भी पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद थी। भाजपा पदाधिकारियों ने जनसभा में करीब 15 हजार लोगों के जुटने का दावा किया था। इसी के अनुरूप कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां की जा रही थीं।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड में स्नातक एमएलसी प्रत्याशी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह और शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी के समर्थन में जनसभा करनी थी। बारिश के चलते मैदान में पानी भरने से कार्यक्रम प्रभावित हुआ।

हालांकि, सुबह से हुई बारिश ने आयोजन की तैयारियों पर पानी फेर दिया। मैदान में पानी भरने के साथ कीचड़ हो जाने से लोगों के बैठने और सभा के संचालन में मुश्किलें पैदा हो गईं। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन और भाजपा संगठन कई स्तरों पर तैयारियों में जुटे थे। कार्यक्रम के दौरान जनसभा के अलावा अन्य निर्धारित स्थलों पर भी मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम था। करीब तीन घंटे के इस दौरे को देखते हुए व्यवस्थाएं की गई थीं।

म्यूजियम का निरीक्षण भी कार्यक्रम में था शामिल

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे में ताजमहल के पूर्वी गेट के पास बन रहे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम का निरीक्षण भी शामिल था। म्यूजियम का करीब 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा होने की जानकारी दी गई थी। इसका उद्घाटन 15 दिसंबर को प्रस्तावित है। म्यूजियम के निर्माण और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारी पहले से तैयारियों में जुटे थे। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने भी निर्माणाधीन परिसर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे।



जनसभा स्थल पर पानी भरने से कीचड़ हो गया।

15 हजार लोगों के जुटने का था दावा

भाजपा पदाधिकारियों के मुताबिक, टाटा ग्राउंड में होने वाली जनसभा में आगरा के साथ आसपास के जिलों से भी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के पहुंचने की तैयारी थी। सभा में करीब 15 हजार लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा था। हालांकि, बारिश और मैदान में पानी भरने के चलते मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया।

नवरात्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद मिशन शक्ति टीम

दुर्गा पंडालों के आसपास गश्त, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की निगरानी,

तमसा संकेत संवाददाता

बलदेव (मथुरा)। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बलदेव थाना पुलिस की मिशन शक्ति टीम सक्रिय नजर आ रही है। नवरात्र के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों, मंदिरों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए मिशन शक्ति टीम द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। टीम का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही उनमें सुरक्षा का विश्वास मजबूत करना है। नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों एवं दुर्गा पंडालों में पहुंचती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मिशन शक्ति टीम सार्वजनिक स्थानों और पंडालों के आसपास निगरानी रख रही है। पुलिस टीम की सक्रियता से असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना की आशंका को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मिशन शक्ति टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है।



महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को प्राथमिकता देते हुए पुलिस की मौजूदगी बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं और बालिकाएं बिना किसी भय के नवरात्र के धार्मिक आयोजनों में शामिल हो सकें। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की इस सक्रियता का उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें यह भरोसा दिलाना है।

फास्ट न्यूज

आगरा में 50 साल पुराना पुल होगा ध्वस्त

आगरा। आगरा शहर के व्यस्ततम ईदगाह-खेरिया रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का नवनिर्माण 17 अक्टूबर से शुरू होगा। पहले इस पुल की मरम्मत की योजना थी, लेकिन 50 वर्ष की अवधि पूरी होने के कारण रेल प्रशासन ने नया पुल बनाने का निर्णय लिया है। निर्माण के चलते 90 दिनों तक सड़क यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि इस आरओबी का निर्माण वर्ष 1970 में हुआ था।

18 रुपये की पानी की बोतल 20 में बेची

अलीगढ़। हाथरस के बीबीसीएन रेस्टोरेंट पर पानी की बोतल की तय कीमत से ज्यादा रकम वसूलने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रेस्टोरेंट ने 18 रुपये एमआरपी वाली बोतल 20 रुपये में बेची थी। इस मामले में अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने आदेश दिया है। रेस्टोरेंट को 5 हजार रुपये अधिवक्ता फीस और एक हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। आदेश का पालन करने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है। मामला 11 मार्च 2026 का है। अलीगढ़ के अधिवक्ता अंकुर अग्रवाल हाथरस के बीबीसीएन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे।

ढिल्लो के लिए भूपेंद्र ने झोंकी ताकत

मुरादाबाद। मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने मुरादाबाद-बरेली शिक्षक एमएलसी सीट से भाजपा के प्रत्याशी हरि सिंह ढिल्लो को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अमरोहा के रहने वाले हरि सिंह ढिल्लो कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह के समधी हैं। उनके समर्थन में भूपेंद्र ने गुरुवार को शहर के कई स्कूल-कॉलेजों में टीचर्स को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की।

मिशन शक्ति-6.0 का उद्देश्य बेटियों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाना

होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज में डांडिया फिएस्टा की धूम

तमसा संकेत संवाददाता

मुजफ्फरनगर। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर जड़ौदा स्थित होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज में 'डांडिया फिएस्टा' का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने पारंपरिक डांडिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। रंग-बिरंगे परिधानों और मनमोहक नृत्य मुद्राओं के बीच छात्राओं ने भारतीय संस्कृति एवं लोक परंपराओं की सुंदर छटा प्रस्तुत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजकीय इंटर कॉलेज, जड़ौदा की प्रधानाचार्य श्रीमती सुचित्रा सैनी, विद्यालय प्रबंधक श्रीमती रीटा दहिया, प्रधानाचार्य श्री प्रवेन्द्र दहिया एवं श्रीमती जोली शर्मा ने मां दुर्गा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर नवरात्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारतीय परंपराओं से जुड़े रहने का संदेश दिया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के दौरान छात्राओं ने 'चोगाड़ा तारा', 'छम्मा-छम्मा नाचे आज ढोल बाजे' और 'नगाड़ा संग ढोल बाजे' जैसे लोकप्रिय गीतों पर शानदार डांडिया नृत्य प्रस्तुत किए। छात्राओं के उत्साह, आत्मविश्वास और बेहतरीन तालमेल ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम की तैयारी में विद्यालय के कोरियोग्राफर विशाल गौतम एवं अनिकेत का विशेष योगदान रहा। उनके मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से छात्राओं ने प्रभावशाली प्रस्तुतियां दीं।



बोले- त्योहार तक एसआईबी सर्वे रोकें, शत-प्रतिशत बिलिंग करने वालों को न करें परेशान

जीएसटी छापों पर भड़के व्यापारी

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। आगरा में जीएसटी विभाग की विशेष जांच शाखा (SIB) के सर्वे और छापेमारी को लेकर व्यापारियों में नाराजगी बढ़ने लगी है। मंगलवार को प्रतिष्ठित ब्रजभोग मिष्ठान भंडार पर हुई छापेमारी में चार करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़े जाने के बाद व्यापारियों ने विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए। बृहस्पति-वार को जयपुर हाउस में आयोजित व्यापारी संवाद कार्यक्रम में कारोबारियों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखीं और त्योहारी सीजन तक SIB के सर्वे स्थगित करने की मांग की। व्यापारियों का कहना था कि दीपावली सहित अन्य त्योहारों के दौरान कारोबार बढ़ जाता है। ऐसे समय में सर्वे और छापेमारी से व्यापार प्रभावित होता है। उन्होंने विभाग से मांग की कि त्योहारों तक कारोबारियों को राहत दी जाए, ताकि वे बिना किसी बाधा के बिक्री कर सकें और राजस्व बढ़ाने में सहयोग दे सकें। जयपुर हाउस में आयोजित व्यापारी संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्वाइंट कमिश्नर एके सिंह ने की। इस दौरान विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने GST सर्वे, माल की ढुलाई, ई-वे बिल और बिक्री में कमी जैसी समस्याएं उठाईं। ज्वाइंट कमिश्नर एके सिंह ने कहा कि दीपावली के दौरान बाजार में कारोबार बढ़ता है। ऐसे में व्यापारियों को अपनी वास्तविक बिक्री के अनुसार रिटर्न दाखिल करना चाहिए। इससे विभाग को राजस्व प्राप्त होगा और व्यापारियों को भी अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।



नो-एंट्री और ई-वे बिल से भी बढ़ रही परेशानी

किराना व्यापारी रमेश कल्याणी ने माल की ढुलाई के दौरान आने वाली समस्याओं को उठाया। उन्होंने बताया कि रावतपाड़ा क्षेत्र में ट्रकों की नो-एंट्री होने के कारण माल रामबाग से टेंपो के माध्यम से दुकानों तक पहुंचाया जाता है। ऐसी स्थिति में मूल ई-वे बिल ट्रक में होने के कारण सचल दल रास्ते में टेंपो को रोक लेता है। इससे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और माल पहुंचाने में देरी होती है। रमेश कल्याणी ने कहा कि बिल मौजूद होने के बावजूद व्यापारियों को जांच संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है। उन्होंने विभाग से मांग की कि माल की ढुलाई से जुड़ी व्यावहारिक दिक्कतों को समझते हुए उचित समाधान निकाला जाए, ताकि व्यापारियों को बेवजह परेशान न होना पड़े।



अक्टूबर से मार्च के बीच होता है 65 प्रतिशत कारोबार

व्यापार मंडल के जय पुरसनानी ने कारोबार के मौसमी स्वरूप का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विभाग को शुरुआती छह महीनों की बिक्री के आधार पर पूरे साल के कारोबार का आकलन नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि व्यापार का करीब 65 प्रतिशत हिस्सा अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। इस अवधि में त्योहारों, शादियों और अन्य आयोजनों के कारण बाजार में मांग बढ़ती है। ऐसे में साल के शुरुआती महीनों में कम बिक्री के आधार पर पूरे वित्तीय वर्ष के कारोबार का अनुमान लगाना उचित नहीं है।

अंबेडकरनगर में दो होनहार छात्राओं को मिला प्रशासनिक नेतृत्व का मौका

मिशन शक्ति : अंशिका बनीं एक दिन की डीएम, अल्का ने संभाली एसपी की भूमिका

तमसा संकेत संवाददाता

अंबेडकरनगर। बेटियां खेल के मैदान में सफलता हासिल करने के साथ प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा सकती हैं। इसी संदेश के साथ मिशन शक्ति अभियान-6.0 के तहत शारदीय नवरात्रि के अवसर पर अंबेडकरनगर की दो होनहार छात्राओं को एक दिन के लिए प्रशासनिक और पुलिस नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली अंशिका को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया, जबकि मंडल स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता की विजेता छात्रा अल्का ने एक दिन की पुलिस अधीक्षक की भूमिका निभाई। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और नेतृत्व कौशल विकसित करना है। अधिकारियों की भूमिका निभाने का अवसर मिलने से छात्राओं को प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से समझने का मौका मिला। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जलालपुर की कक्षा सात की छात्रा अंशिका पुत्री आशाराम को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। अंशिका ने प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता-2026 में अंडर-14 आयु वर्ग के 46 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित कर चुकी अंशिका को प्रशासनिक नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपकर बालिकाओं को यह संदेश दिया गया कि मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर वे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं।



पुलिस अधीक्षक की भूमिका में अल्का की भागीदारी का उद्देश्य बालिकाओं को पुलिस व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा के महत्व से परिचित कराना था। इस पहल के जरिए उन्हें भविष्य में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

डीएम ईशा प्रिया और एसपी प्राची सिंह के साथ किया पैदल मार्च

इस अवसर पर एक दिन की जिलाधिकारी अंशिका और एक दिन की पुलिस अधीक्षक अल्का ने जिलाधिकारी ईशा प्रिया, पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह तथा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं उपजिलाधिकारी अकबरपुर प्रतीक्षा सिंह के साथ कटेहरी बाजार में पैदल मार्च किया। स आयोजन के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन तथा नारी सशक्तीकरण का संदेश दिया गया। अधिकारियों के साथ छात्राओं की भागीदारी ने उन्हें सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को समझने का व्यावहारिक अनुभव भी दिया।

एमआईईटी में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, विद्यार्थियों को बताए बचाव के तरीके

सोशल मीडिया फ्रॉड और डिजिटल अपराधों से सतर्क रहने के लिए किया जागरूक

तमसा संकेत संवाददाता

मेरठ। एमआईईटी में मेरठ पुलिस की साइबर सेल की टीम ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। साइबर सेल प्रभारी संजय पांडेय के नेतृत्व में सब-इंस्पेक्टर आकाश पंवार, हेड कांस्टेबल उमेश कुमार और हेड कांस्टेबल मोहित पवार ने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के विभिन्न तरीकों और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी। कार्यक्रम में संजय पांडेय ने वित्तीय धोखाधड़ी, सोशल मीडिया फ्रॉड, सिम स्वैपिंग, फर्जी एसएमएस और केवाईसी लिंक के जरिए होने वाली ठगी के बारे में बताया।

उन्होंने विद्यार्थियों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने तथा ओटीपी, पासवर्ड और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करने की सलाह दी। संदिग्ध वेबसाइट की जांच के लिए वायरस टोटल जैसे ऑनलाइन टूल के उपयोग की जानकारी भी दी गई।



विद्यार्थियों को सिम स्वैपिंग से बचाव, संचार साथी पोर्टल की सुविधाओं और आधार की सुरक्षा के लिए यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध बायोमेट्रिक लॉक सुविधा के बारे में भी बताया गया। इसके साथ ही साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग और महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों की पहचान तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया समझाई गई। साइबर सेल की टीम ने बताया कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। समय पर शिकायत करने से ठगी की रकम को आगे हस्तांतरित होने से रोकने में मदद मिल सकती है।

पृष्ठ 01 का शेष...

सीजेपी के तिरंगा...

वे बोले कि आप लोगों को भड़का रहे हैं। आप तिरंगा लहराने जा नहीं सकते। मतलब अपने ही देश में तिरंगा लहराने से मना किया जा रहा है। कॉकरोच पार्टी के 'तिरंगा लहरा दो' मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि अभिजीत दीपके को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हाथ में रखने के लिए हिरासत में लिया गया है। जरा सोचिए, स्वतंत्र भारत में हमारे युवाओं को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने पर हिरासत में लिया जा रहा है। यह किसी अघोषित आपातकाल से कम नहीं है। असहमति से डरने वाली सरकार अब पूरी पीढ़ी को चुप कराने के लिए डराने की कोशिश कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि अभिजीत दीपके को केवल इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वह राष्ट्रीय ध्वज लेकर निर्धारित स्थान की ओर जा रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी के अनुसार, यह कार्रवाई दिखाती है कि प्रशासन को किसी अव्यवस्था से नहीं, बल्कि आम नागरिकों के हाथों में तिरंगे की शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ताकत से डर है। अभिजीत दीपके जहां ठहरे हुए थे, पुलिस वहां पहुंची थीं। दीपके और पुलिस की बहस भी हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दीपके ने कहा था कि आप अपनी मर्जी से जो मन में आ रहा है, वही लिख रहे हैं। यह बेतुका है। फांसी पर चढ़ा दो ना। क्या मजाक है ये? नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक BNSS की धारा 163 लागू है। इसलिए, हम सभी से कानून का पालन करने की अपील करते हैं। मुंबई के आजाद मैदान में CJP के 'लेहरा दो तिरंगा' विरोध प्रदर्शन के लिए लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। दिल्ली के डीसीपी स्पेशल सेल नर्रा चैतन्य ने कहा, सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। फिलहाल, आप देख सकते हैं कि स्थिति बहुत शांतिपूर्ण है। दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को भेजे गए नोटिस में सीजेपी के पिछले आचरण और सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान का हवाला दिया गया है।

सरकार इस महीने...

लेकिन इसका अब तक सत्रावसान नहीं किया गया है। लोकसभा में 543 सांसद हैं। 3 सीटें खाली हैं। इनमें से NDA के 318 सांसद हैं। बिल को पास कराने के लिए दो-तिहाई यानी 360 वोट चाहिए। अगर डीएमके के 22 सांसद बिल का समर्थन करते हैं तो बिल के समर्थन में 340 सांसद हो जाएंगे। यानी इसके बाद भी भाजपा को लगभग 20 सांसदों की जरूरत है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं। 3 खाली हैं। इस तरह 240 में से NDA के 153 सांसद हैं। यहां बिल को पास कराने के लिए 162 सांसद चाहिए। यानी, यहां भी NDA को छोटी पार्टियों के 9 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। अब केंद्र सरकार DMK से समर्थन लेने के लिए बातचीत कर रही है। तमिलनाडु चुनाव के बाद DMK का कांग्रेस से अलगाव हो चुका है। इसके बाद DMK INDIA ब्लॉक से भी अलग हो गई। सूत्रों ने बताया कि सरकार कुछ छोटे दलों के संपर्क में भी है। इन दलों से बातचीत का मकसद सदन में सरकार के संख्या बल को मजबूत करना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परिसीमन बिल पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव संसद में रखने से पहले सभी दलों से चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में खड़गे ने चेतावनी दी कि सरकार को व्यापक संविधान संशोधन बिल को फिर जबरन पास कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोशिश पहले भी नाकाम रही है। खड़गे ने मानसून सत्र समापन नहीं होने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को सत्र अनिश्चित-काल के लिए स्थगित होने के 64 दिन बाद भी लोकसभा और राज्यसभा का सत्रावसान नहीं हुआ है। संसद के मानसून सत्र की अंतिम बैठक 13 अगस्त को हुई थी। इसके दो महीने बाद अब तक सेशन औपचारिक रूप से खत्म होने की घोषणा नहीं हुई है। दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के बिना सत्रावसान रहने की यह सबसे लंबी अवधि है। इससे पहले 1989 में दोनों सदन 63 दिन ऐसी स्थिति में रहे थे। सरकार ने इसे पहले परिसीमन और महिला आरक्षण को पास कराने के लिए 15 से 17 अप्रैल तक तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया था। लेकिन इस दौरान बिल पास नहीं हो पाया था।

'सपा ने राज्यसभा...

इस चुनाव में मेरठ और सहारनपुर मंडल के मतदाताओं द्वारा वोट किया जाएगा। इस कार्यक्रम से पहले सीएम को इंदिरापुरम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निरीक्षण करने जाना था, हालांकि कार्यक्रम रद्द हो गया। योगी ने कहा- आज डबल इंजन सरकार में विरासत का अद्भुत संगम देख रहे होंगे। काशी विश्वनाथ और मां विध्यवासिनी में भव्य कॉरिडोर बन गया। अयोध्या में श्रीराम का भव्य मंदिर बन गया। मथुरा-वृंदावन का विकास नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। सहारनपुर में मां शांकभरी देवी मंदिर में भव्य कॉरिडोर बन रहा है। अक्सर शिवालिक पहाड़ियों में पानी आने के कारण श्रद्धालुओं में भय रहता था। इस साल के बाद वहां पर हम एलिवेटेड रोड बनाकर पूरा करेंगे, फिर किसी भी समय जाकर दर्शन कर सकेंगे। सीएम ने कहा- अलीगढ़, मुरादाबाद, आजमगढ़, बलरामपुर, मिर्जापुर और सहारनपुर में विश्वविद्यालय नहीं थे, इन जगहों पर विश्वविद्यालय बनवाया। खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बनवाया। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बनवाया। बुंदेलखंड में दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय बनवाया।

हम एसआईआर...

इस दौरान भाजपा के पूर्व सांसद राजपाल और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरबीर मलिक ने पार्टी जॉइन की। अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा के आधार वोटर उससे दूर हो रहे हैं। सनातनी, महिलाएं, मध्यम वर्ग और युवा भी उससे नाराज हैं। इसी वजह से अब चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में साजिश की जा रही है। बताया कि समाजवादी पार्टी ने 100 विधानसभा क्षेत्रों का डेटा चुनाव आयोग को दिया है जिसमें गड़बड़ियां भाजपा ने की या कराई है। अखिलेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 17 और 24 अक्टूबर को बूथों पर चलने वाले अभियान के दौरान मतदाताओं के नाम जुड़वाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। सपा प्रमुख ने मांग की कि SSR के बाद दूसरा रिवीजन नहीं होना चाहिए। आरोप लगाया कि चुनाव आयोग से सवाल पूछने पर भाजपा जवाब देने लगती है। उन्होंने TCS जैसी कंपनी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के कई वर्गों के मतदाता उससे नाराज हैं। उनके मुताबिक, चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी के आरोपों से सनातनी मतदाता दुखी हैं।

सुप्रीम कोर्ट की...

उन्होंने सुझाव दिया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय गाड़ियों और पैदल चलने वालों की आवाजाही का अध्ययन करे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रम बनर्जी ने कहा कि रेड लाइट लगाना पर्याप्त है, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि और इंतजाम की जरूरत है, तो केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह लोगों की जान का सवाल है। हम दोनों वहां जाएंगे। पिछले साल जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के पास पैदल सड़क पार करने की सही व्यवस्था नहीं होने पर चिंता जताई थी। सड़क सुरक्षा सुधारने के लिए यह याचिका हड्डियों के विशेषज्ञ डॉक्टर एस. राजसीकरन ने 2013 में दायर की थी। कोर्ट ने कहा था कि इस व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल, फुट ओवरब्रिज और सुरक्षा के दूसरे इंतजाम नहीं होने से सड़क पार करने वाले लोगों की जान को खतरा रहता है।

पैनिक अटैक से चेहरा टेढ़ा हो जाता था, बोलना मुश्किल था, 26 दिन रिहैब सेंटर में रहा

तलाक के बाद शराब की लत लगी : चहल

बयान

नई दिल्ली। भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने शराब की लत, तलाक और पैनिक अटैक पर बात की। उन्होंने आकाश चोपड़ा के पॉडकास्ट में बताया कि धनश्री वर्मा से तलाक के बाद उनकी शराब की लत हद से ज्यादा बढ़ गई थी। वे 26 दिन रिहैब सेंटर में रहे थे।

36 साल के चहल ने बताया कि पैनिक अटैक के दौरान उनका चेहरा सिकुड़कर टेढ़ा हो जाता था। इससे बोलना भी मुश्किल होता था।

चहल 3 साल से टीम इंडिया से बाहर हैं। उन्होंने पिछला टी-20 इंटरनेशनल मैच अगस्त 2023 में खेला था। उन्होंने 15 दिन पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लिया था। चहल के मुताबिक, इस फैसले से उनकी निजी जिंदगी में बड़ा



युजवेंद्र चहल और उनकी एक्स वाइफ धनश्री की मास्क वाली फोटोज 20 मार्च 2025 की हैं। जब चहल और धनश्री फैमिली कोर्ट में फैसले के लिए पहुंचे थे। इसी दिन तलाक को मंजूरी मिली थी।

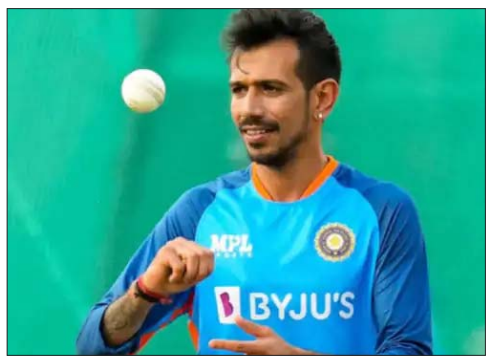
बदलाव आया। उनकी समझ बढ़ी और भावनाएं संतुलित हुईं। उन्होंने कहा, "पिछले IPL में मेरा शरीर फिर 30 साल का महसूस हो रहा था। मैं जिम कर रहा था, फील्डिंग ड्रिल कर रहा था और ठीक से ट्रेनिंग कर रहा था।'

पैनिक अटैक में होंठ कसकर एक तरफ खिंच जाते थे- चहल

चहल ने पैनिक अटैक के बारे में बताया, 'एंग्जायटी में दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मेरा चेहरा सिकुड़ जाता था।' उन्होंने कहा, 'मैं बोल भी नहीं पाता था। मेरा होंठ कसकर एक तरफ खिंच जाता था। चहल ने कहा कि इससे लोग समझ जाते थे कि उनके साथ कुछ गलत है। उन्हें डर था कि सोशल मीडिया पर लोग कई तरह की बातें करेंगे। चहल ने कहा, 'मैंने सोचा कि IPL पर ध्यान देते हैं।'

तलाक के बाद मानसिक स्थिति बिगड़ी- चहल

चोपड़ा ने पूछा कि शराब पीना कैसे और क्यों शुरू हुआ। चहल ने कहा, 'शुरुआत में मैं युवा था। पार्टियां होती थीं। मैंने 2011 में अपना पहला IPL खेला था।' एबी डिविलियर्स ने एक बार उनसे कहा था, 'जिंदगी में संतुलन जरूरी है।' चहल ने कहा कि यह बात सुनने में आसान है, लेकिन अपनाना आसान नहीं होता।



चहल ने अगस्त 2023 में अपना पिछला टी-20 इंटरनेशनल मैच खेला था।

चहल ने कहा- कठिन समय में दोस्त और परिवार हमेशा साथ रहा

आकाश चोपड़ा ने चहल से पूछा कि निजी जिंदगी की परेशानियों के दौरान उनके साथ कौन था। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भावनात्मक चोट, पेशेवर जिंदगी के संकट से अलग होती है। चहल ने जवाब दिया, 'मेरे सबसे अच्छे दोस्त और परिवार मेरे साथ थे।' शराब छोड़ने पर चहल ने कहा, 'पिछले साल काउंटी क्रिकेट के बाद मैंने शराब छोड़ने का फैसला किया। बात हद से ज्यादा बढ़ गई थी।' उन्होंने कहा, 'मैंने रिहैब सेंटर में दाखिला लिया और 26 दिन वहां रहा। अब मुझे पता है कि इसे कैसे संभालना है।'

> चहल ने कहा, 'तलाक के बाद चीजें हद से ज्यादा बढ़ गई थीं। मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।' उन्होंने कहा, 'मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इसी रास्ते पर चलता रहा, तो जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है, उस क्रिकेट को बर्बाद कर दूंगा।'

4 साल में चहल-धनश्री की शादी टूटी

(रिश्ते की टाइम लाइन)



- **जून 2020** : लॉकडाउन के दौरान चहल और धनश्री की मुलाकात हुई। डांस क्लास के दौरान दोनों में प्यार हो गया।
- **दिसंबर 2020** : चहल और धनश्री ने शादी कर ली। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को शादी की जानकारी दी थी।
- **जून 2022** : दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए। तलाक की खबरें पहले सोशल मीडिया पर आईं। दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया था।
- **फरवरी 2025** : मुंबई की फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगाई। फैमिली कोर्ट ने छह महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड का समय दिया। इसके खिलाफ चहल ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
- **मार्च 2025** : बॉम्बे हाईकोर्ट ने चहल की याचिका पर फैमिली कोर्ट को 20 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया था। 4.75 करोड़ रुपए की एलिमनी पर सेटलमेंट हुआ और दोनों का तलाक हो गया।

पिच फ्लैट बनाएं, बाउंड्री छोटी करें : संजय मांजरेकर

बॉलर्स के खिलाफ नियम सख्त करने की जरूरत, ताकि हर मैच में 300 रन बने

नई दिल्ली। 'मुझे लगता है कि पिचों को और फ्लैट बनाने, बाउंड्री छोटी करने और गेंदबाजों के खिलाफ नियम और सख्त करने की गुंजाइश है, ताकि टी-20 में नियमित रूप से 20 ओवर में 300 रन बन सकें।' यह कहना है पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर का। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पोस्ट के जरिए कही।

मांजरेकर की पोस्ट ऐसे समय आई है, जब फ्लैट भारतीय पिचों पर सवाल उठ रहे हैं। गौतम गंभीर, युजवेंद्र चहल जैसे कई दिग्गज क्रिकेटर्स पिचों को बॉलिंग फ्रेंडली बनाने की मांग कर रहे हैं।

एक दिन पहले भारतीय टीम के पूर्व चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने कहा- 'टी-20 क्रिकेट में बैटिंग पिचों



से बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बिगड़ रहा है।'

नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में चेतन ने कहा- 'मैं मानता हूं कि गेंदबाज रन देने के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन उन्हें इतना मत मारिए कि वे दोबारा मैदान पर आना ही न चाहें।'

9 अक्टूबर की रात को रांची में दूसरे टी-20 के बाद गंभीर ने कहा था- 'फ्लैट पिचों पर गेंदबाजों के करियर दांव पर लगे हैं। सरफेस में बैट और बॉल के बीच बराबरी का मुकाबला होना जरूरी है।'

3 अक्टूबर को गुवाहाटी में दूसरे वनडे के बाद गंभीर ने कहा था कि 'यह क्रिकेट नहीं था, सिर्फ बल्लेबाजी थी।' उस मुकाबले में भारत ने 406 रन का लक्ष्य हासिल किया था। इस मुकाबले में 811 रन बने थे। संजय मांजरेकर भारतीय कमेंटेटर हैं, जोकि अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्हें तकनीकी रूप से मजबूत बैटिंग स्किल के लिए भी जाना जाता है। वे क्रिकेटर्स को स्पेशलाइज ट्रेनिंग देते हैं।

मांजरेकर 37 मैचों के टेस्ट करियर में 2043 रन बनाए।

चेतन शर्मा बोले- गेंदबाजों के लिए मददगार पिचें बनाए बीसीसीआई

नई दिल्ली। BCCI के पूर्व चीफ सिलेक्टर और क्रिकेटर चेतन शर्मा ने BCCI से गेंदबाजों के लिए मददगार पिचें बनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा- 'टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाजों के अनुकूल पिचों से बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बिगड़ रहा है।'

चेतन ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा- 'मैं मानता हूं कि गेंदबाज रन देने के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन उन्हें इतना मत मारिए कि वे दोबारा मैदान पर आना ही न चाहें।' चेतन ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसी पिचें होनी चाहिए, जिन पर गेंदबाज अटैकिंग बल्लेबाजों का मुकाबला कर सकें। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में गेंदबाजों की मददगार पिचों की तरह इंटरनेशल में भी ऐसी पिचें तैयार करने पर जोर दिया। चेतन शर्मा ने जमीनी स्तर पर टी-20 क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता को स्वीकार किया। हालांकि, उन्होंने युवा खिलाड़ियों के विकास के लिए रेड-बॉल क्रिकेट को जरूरी बताया।

कहा- सवाल पूछिए, यह अनुशासनहीनता नहीं, सीखने की प्रोसेस

बिंद्रा ने एथलीट्स के खुलकर न बोलपाने पर चिंता जताई

नई दिल्ली, एजेंसी

ओलिंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट शूटर अभिनव बिंद्रा ने एथलीट्स के खुलकर न बोल पाने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा- 'समय के साथ खिलाड़ी अपने मन में भी सवाल करना बंद कर देते हैं।'

बिंद्रा ने एथलीट्स को सवाल पूछते रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपने काम, कोच, तरीकों और सिस्टम पर सवाल उठाएं।

बिंद्रा ने कहा कि खिलाड़ियों का खुलकर बोलना जरूरी है। कुछ लोग इसे अनुशासनहीनता मान सकते हैं, लेकिन यह बेहतर प्रदर्शन के लिए जरूरी हो सकता है। बिंद्रा ने शुक्रवार को सोशल प्लेटफॉर्म X पोस्ट में अपनी बात रखी।



जब एथलीट्स को लगता है कि वे खुलकर नहीं बोल सकते, तो समय के साथ इससे कहीं ज्यादा गंभीर समस्या पैदा होती है। वे धीरे-धीरे अपने मन में भी सवाल करना बंद कर देते हैं। ऐसा होने पर खेलों में उत्कृष्टता के लिए जरूरी कुछ खो जाता है। देश को ऐसे एथलीट्स चाहिए, जो अपने काम, कोच, उन्हें सुझाए गए तरीकों और उनके आसपास मौजूद व्यवस्थाओं पर सवाल करें। यह विरोध के लिए नहीं, बल्कि सच में सुधार की इच्छा से होना चाहिए।

> 44 साल के बिंद्रा को भारत से निकले महान खिलाड़ियों में गिना जाता है। वे ओलंपिक चैंपियन होने के साथ-साथ विश्व चैंपियनशिप के पूर्व गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं।
>
> सक्रिय खेलों से विदा लेने के बाद बिंद्रा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एथलीट्स कमीशन के वाइस-चेयर बने। उन्होंने इस पद पर आठ साल काम किया। उनका कार्यकाल इस साल की शुरुआत में खत्म हुआ।

4 पॉइंट्स में अभिनव बिंद्रा की बात

मैंने अपने खेल करियर में कोचों से सवाल किए और विचारों को चुनौती दी। ऐसा अनादर के कारण नहीं, बल्कि समझने, सीखने और बेहतर होने के लिए किया। मैंने अपने पूरे खेल करियर में कोचों से सवाल किए, विचारों को चुनौती दी और जिज्ञासु बना रहा। ऐसा इसलिए नहीं था कि मेरे मन में सम्मान की कमी थी। मैं समझना, सीखना और बेहतर होना चाहता था।'

मनोरंजन

एक्टर यश को 'बॉस' कहकर पुकारा, 'जय श्री राम' बोलकर की स्पीच की शुरुआत

रणबीर कपूर ने कन्नड़ में की बात, फिर मांगी माफी

नई दिल्ली। बेंगलुरु में नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' के दूसरे ट्रेलर का लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम रणबीर कपूर ने 'जय श्री राम' के नारे से अपना भाषण शुरू किया और कन्नड़ भाषा में बोलकर वहां मौजूद लोगों का सम्मान किया। वहीं रणबीर ने साउथ सुपरस्टार यश को 'यश बॉस' कहकर संबोधित किया। इवेंट में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह और निर्देशक नितेश तिवारी मौजूद रहे। निर्माताओं की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 'रामायण'



दो हिस्सों में रिलीज की जाएगी। फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगा। पहले भाग में भगवान राम और रावण की कहानियां अलग-अलग चलेंगी, जिससे इस पार्ट में दोनों का आमना-सामना नहीं होगा। वहीं, दोनों के बीच होने वाले ऐतिहासिक युद्ध के दृश्य अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाले दूसरे पार्ट में दिखाए जाएंगे।

यश ने फैंस से एकजुट होने के लिए कहा

अपने संबोधन के दौरान अभिनेता यश ने लोगों से आपसी भेदभाव भूलकर एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर हम 'बांटो और राज करो' की तरह आपस में ही लड़ते रहे, तो दुनिया का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे।

यश ने कन्नड़भाषियों और पूरे दक्षिण भारत के दर्शकों से 'रामायण' फिल्म का समर्थन करने का आग्रह करते हुए कहा कि जब नीयत सही हो, तो सभी को साथ खड़े होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में भगवान राम के महत्व पर बात करते हुए उन्होंने लोगों से इस पौराणिक गाथा को बड़े पर्दे पर देखने का आग्रह किया।

> इवेंट में जब रणबीर कपूर स्टेज पर पहुंचे तो उन्होंने 'जय श्री राम' बोलकर अपने भाषण की शुरुआत की फिर कन्नड़ भाषा में बोलना शुरू किया। थोड़ी कन्नड़ बोलने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए जनता से माफी भी मांगी।
> रणबीर ने अपने अंदाज में कहा कि इस बार वे इतनी ही भाषा सीखकर आ पाए हैं और अगली बार 'यश बॉस' से थोड़ी ज्यादा कन्नड़ सीखकर आएंगे।



रजनीकांत की 'जेलर 2' ने पहले दिन 125 करोड़ कमाए

वर्ल्डवाइड ओपनिंग में 'एनिमल' का रिकॉर्ड तोड़ा

नई दिल्ली। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की एक्शन-ड्रामा फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुरुआत की है। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 15 अक्टूबर को रिलीज के पहले दिन भारत में 59.70 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है।

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने देश भर में 16,599 शो से 70.25 करोड़ रुपए का डोमेस्टिक ग्रॉस और 55 करोड़ रुपए का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसके साथ ही फिल्म का पहले दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 125.25 करोड़ रुपए पहुंच गया है

विदेशों में कमाई के मामले में 'जेलर 2' ने इस साल जनवरी में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 'धुरंधर 2' ने पहले दिन ओवरसीज में 52 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था, जबकि 'जेलर 2' ने 55 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। वहीं, 125.25 करोड़ रुपए के कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ इसने रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' (116 करोड़ रुपए वर्ल्डवाइड ओपनिंग) का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है। फिल्म को पहले दिन सिनेमाघरों में करीब 37.46 लाख (3,746,734) दर्शक मिले।



पाकिस्तानी फैन चाकू लिए घर में घुसा, पिता को हार्ट अटैक आया, जन्म से पहले मां ने रखा नाम

78 की हुई हेमा मालिनी

मुंबई, एजेंसी

16 अक्टूबर 1948

आज से 78 साल पहले तमिलनाडु के अम्मानकुड़ी में जया लक्ष्मी प्रसव के आखिरी चरण में थीं। दो बेटे पहले से थे, तो तीसरे बच्चे के जन्म से पहले ही उन्होंने पति वी.एस.आर.चक्रवर्ती से कहा- 'देखना, बेटी ही होगी। मैं उसका नाम हेमा मालिनी रखूंगी, जो बड़ी होकर क्लासिकल डांसर बनेगी।'

कमरे में दुर्गा, सरस्वती के बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए।

जया लक्ष्मी की कही बात सच साबित हुई, अस्पताल में किलकारी गूंजी, बेटी हुई थी। नाम रखा गया हेमा मालिनी, जिसे आज पूरा देश ड्रीम गर्ल के नाम से भी जानता है।

मां के फैसले के अनुसार, हेमा मालिनी पहले क्लासिकल डांसर बनीं और फिर हीरोइन, लेकिन यही स्टारडम वजह रहा कि उन्होंने अपने पिता को खो दिया। वजह रही एक पाकिस्तानी फैन का घर में घुसना और फिर किचन नाइफ से दहशत फैलाना।



तुम हसीन मैं जवां फिल्म के टाइटल सॉन्ग की झलक।

हेमा मालिनी ने होश संभाला ही था कि मां ने उनका दाखिला क्लासिकल डांसिंग में करवा दिया। खेल-कूद की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। स्कूल से लौटते ही हेमा कभी डांस क्लास, तो कभी सिंगिंग क्लास जातीं। कोई टीचर सिखाने में कोताही बरतता, तो मां तुरंत क्लासेस बदल देतीं। कुछ सालों बाद परिवार दिल्ली आकर बसा। क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग यहां भी जारी रही। हर आम बच्चे की तरह हेमा भी दिनभर खेलना चाहती थीं, लेकिन मां ने कुछ अलग सोच रखा था।

वो हेमा के बालों में तेल डालकर चोटी बनातीं, बालों में फूल लगातीं, आंखों में काजल। टिपिकल मद्रासी लड़की की तरह घाघरा चोली पहनातीं। मां उन्हें सही ढंग से कपड़े पहनना और हाव-भाव की सीख देतीं।

जब इस तरह वो कभी दिल्ली की सड़कों पर निकलतीं, तो आसपास से गुजरने वाले लोग उनका मजाक उड़ाते। हेमा इससे नाराज होतीं, तो मां कहतीं- 'वह तुम्हें साउथ इंडियन कहते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है, तुम साउथ इंडियन ही हो।' कुछ साल बीते ही थे कि क्लासिकल डांस ट्रेनिंग सही ढंग से न मिल पाने के डर से जया लक्ष्मी ने पति से साफ कह दिया कि वह अपना ट्रांसफर मद्रास करवा लें। परिवार मद्रास आ गया। जल्द ही हेमा स्टेज शोज करने लगीं।

एक ऐसे ही स्टेज शो में 13 साल की हेमा पर तमिल डायरेक्टर सीवी श्रीधर की नजर पड़ी। उन्होंने झट से हेमा को अगली फिल्म में कास्ट कर लिया। शूटिंग शुरू हुई। हेमा बड़े उत्साह के साथ 2 दिनों तक शूटिंग के सेट पर गईं। डायरेक्टर उनके नाम से नाखुश थे। सुझाव मिला कि नाम हेमा मालिनी की जगह सुजाता रख लिया जाए। फिर तीसरे दिन उन्हें ये कहकर फिल्म से निकाल दिया गया कि तुम बहुत दुबली-पतली हो, कभी हीरोइन नहीं बन पाओगी।13 साल की बच्ची के लिए ये रिजेक्शन काफी भावुक रहा। मां ने तब मनोबल बढ़ाते हुए कहा- ये बस एक चैलेंज है, जिसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। हेमा फिर मंच पर लौट गईं।

कुछ समय बाद 1963 की फिल्म इंदु साथियम में हेमा मालिनी को एक गाने में डांस करने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें कई तमिल फिल्मों में छोटे रोल दिए जाने लगे।



कोकीन के नशे में बेहोश मिली थी, 3 साल के बच्चे को अकेला छोड़ दिया था

यूएई शाही परिवार की बहू को रिहैब कैंप भेजा गया

सजा

लंदन, एजेंसी

UAE के शाही परिवार से जुड़ी 32 साल की महराह अल नाहयान को लंदन में बच्चे की देखभाल में लापरवाही के मामले में सजा सुनाई गई है। उन्हें दो साल तक रिहैब कार्यक्रम में शामिल होना होगा। साथ ही करीब 7.7 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

यह मामला 13 जून का है। उस दिन महराह पश्चिमी लंदन की एक सड़क पर बेहोश मिली थीं। उनके पास उनका 3 साल का बच्चा बिना जूते पहने स्कूटर से खेल रहा था। बच्चा व्यस्त सड़क पर चल रही गाड़ियों के करीब था। कोर्ट में महराह ने माना कि उन्होंने कोकीन का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने महराह के बैग की तलाशी ली। उसमें नशे के इस्तेमाल से जुड़ा सामान मिला, लेकिन कोई गैरकानूनी नशीला पदार्थ नहीं मिला। मंगलवार को लंदन के साउथवार्क क्राउन कोर्ट में महराह ने बच्चे की देखभाल में लापरवाही करने का जुर्म कबूल किया। जज जेरेमी जॉनसन ने कहा कि जब महराह बेहोश थीं, तब बच्चे की जान को खतरा था। जज के मुताबिक, बच्चा सड़क पर भटक सकता था, खो सकता था या कोई अनजान व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचा सकता था। इस घटना से बच्चा डर भी सकता था।



अबू धाबी के शाही परिवार की बहू 13 जून को लंदन की सड़क पर बेहोश मिली थी।

सड़क किनारे 30 मिनट तक बेहोश पड़ी रहीं

कोर्ट में बताया गया कि 13 जून को महराह लोहे की रेलिंग के सहारे बेहोश पड़ी थीं। उनके पास ही एक अन्य व्यक्ति भी बेहोश था। वहीं, उनका 3 साल का बच्चा अकेले खेल रहा था।

वहां से गुजर रहे लोगों ने बच्चे को अकेला देखा तो उसकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने पुलिस के पहुंचने तक बच्चे को अपने पास रखा। इस दौरान एक व्यक्ति ने घटना का वीडियो भी बनाया था। कोर्ट के मुताबिक, महराह करीब 30 मिनट तक बेहोश रहीं। होश आने पर उन्होंने लोगों से पूछा कि वे इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह कोई कत्लखाना नहीं है। आपको इतनी परवाह क्यों है? आप इतने परेशान क्यों हैं?"

वकील ने कहा- घटना वाले दिन नशा नहीं किया था

कोर्ट में बताया गया कि महराह ने बेहोश मिलने से पहले के कुछ दिनों में कोकीन ली थी। हालांकि, उनके वकील स्टीफन वुलो ने कहा कि उन्होंने घटना वाले दिन नशा नहीं किया था। वकील के मुताबिक, पिछले दिनों नशा करने के कारण वह बहुत थक गई थीं। वकील ने कोर्ट को बताया कि महराह को अपनी गलती का पछतावा है और वह नशे की लत छोड़ना चाहती हैं। वह तीन महीने का इलाज करा रही थीं, जो अक्टूबर के आखिर तक पूरा होना था।

घटना के बाद से महराह सरे के वोकिंग इलाके में प्रायरी क्लिनिक में नशे की लत का इलाज करा रही हैं। इलाज के बाद उनकी गिल्डफोर्ड इलाके में घर किराए पर लेने की योजना है। वहां वह दिन में इलाज कराएंगी और नशे की लत छोड़ने में मदद करने वाले समूह नारकोटिक्स एनोनिमस की बैठकों में शामिल होंगी।



महराह के कुछ दूर एक आदमी भी नशे में सड़क किनारे बेहोश मिला था।

यात्रियों को महंगे फ्लाइट टिकटों से मिलेगी राहत

मनमाने किराए को कंट्रोल करने के नए नियम फाइनल

नई दिल्ली, एजेंसी

यात्रियों को महंगे फ्लाइट टिकटों से जल्द ही राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने एयरलाइंस के मनमाने किराए को कंट्रोल करने के लिए नए नियमों को फाइनल कर लिया है। सरकार दो हफ्ते में इन नए नियमों को जारी करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि जारी नियमों को 16 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर कोर्ट के सामने पेश किया जाए। इस फैसले का सीधा असर शेयर बाजार पर भी दिखा। इंडिगो एयरलाइन को चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में आज 2% की गिरावट आई। सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट एयर-लाइंस की ओर से वसूले जाने वाले मनमाने किराए को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस अपारेश सिंह की बेंच को नए नियमों की स्थिति बताई। सॉलिसिटर जनरल ने बेंच से कहा कि हवाई किराए को कंट्रोल करने के नियमों को फाइनल कर दिया गया है और इन्हें सरकारी मंजूरी भी मिल चुकी है। इन नियमों को अगले दो हफ्तों के भीतर पब्लिश कर दिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने मामले को 16 नवंबर को सुनवाई के लिए लिस्टेड करते हुए सरकार को पब्लिश नियमों को सामने रखने का आदेश दिया।



फास्ट न्यूज

अमेरिका: भारतीय मूल के पति की हैवानियत

वाशिंगटन। अमेरिका के शिकागो से एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है। यहां भारतीय मूल के एक 31 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी 32 वर्षीय अलग रह रही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की वजह यह थी कि महिला ने अपने एक पूर्व सहकर्मी के साथ रिश्ते में होने की बात कही और उसके साथ दोबारा साथ रहने से साफ इनकार कर दिया था।

पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 5 गुना बढ़ी, 2.50 हुई

नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 5 गुना टैक्स बढ़ा दिया है। वहीं, डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को लगभग आधा कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने देश में फ्यूल की कमी न हो इसलिए नई दरें आज यानी 16 अक्टूबर से लागू कर दी हैं। नए टैक्स अगले दो हफ्तों तक लागू रहेंगे। इस टैक्स का असर सिर्फ विदेश बेचे जाने वाले पेट्रोल-डीजल पर पड़ेगा। हमारे देश के पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बदलेंगे।

इंटरनेट सनसनी 'जैकी' की मौत के कारण का खुला राज

वाशिंगटन। कैलिफोर्निया में वन्यजीव प्रेमियों और इंटरनेट की दुनिया की मशहूर गिद्ध प्रजाति का बाज 'जैकी' की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई थी। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्डलाइफ ने हाल ही में इसकी पुष्टि करते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की है। बता दें कि जैकी की मौत पिछले साल अगस्त में हुई थी।

कॉम्पिटीशन से कभी नहीं डरे, स्टारलिंक का स्वागत : रिलायंस

मुंबई, एजेंसी

सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस 'स्टारलिंक' की भारत में एंट्री को लेकर चल रहे विवाद के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को कहा कि वह कॉम्पिटिशन से नहीं डरते। कंपनी ने X पर पोस्ट कर कहा कि असली मुकाबला वही है, जिससे यह पता चले कि सबसे अच्छी सर्विस कौन दे रहा है।

कंपनी ने यह बयान इलॉन मस्क की ओर से लगाए गए उन आरोपों के बाद जारी किया, जिनमें उन्होंने भारतीय टेलिकॉम कंपनियों पर स्टारलिंक का रास्ता रोकने का दावा किया था।

इलॉन मस्क भारत में स्टारलिंक की लॉन्चिंग में हो रही देरी को लेकर पिछले कुछ दिनों से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस देरी के लिए वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जिम्मेदार बता रहे हैं और उनके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं।



मस्क का आरोप था- मुकेश अंबानी ने भारत में कंपनी की एंट्री रुकवाई

हाल ही में मस्क ने अपने एक पोस्ट में मुकेश अंबानी पर तंज कसते हुए उन्हें 'प्राइम मिनिस्टर अंबानी' लिखा था। इस पोस्ट में उन्होंने अंबानी को भारत का रियल बॉस बताया था।

मस्क की पोस्ट के बाद कुछ लोगों ने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे सस्ता और तेज इंटरनेट मौजूद है। यहां सिर्फ 300-400 महीने में 60GB डेटा मिल जाता है, जो दूरदराज के गांवों में भी बेहतरीन काम करता है।

12 मिनट तक पूरे जापान में अफरातफरी रही, फिर मौसम एजेंसी ने माफी मांगी

रूस में 7 तीव्रता का भूकंप

कामचटका, एजेंसी

रूस के कामचटका प्रायद्वीप में शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे 7 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।

इसके कुछ देर बाद जापान की मौसम एजेंसी ने गलती से 9.9 तीव्रता के भूकंप की चेतावनी जारी कर दी। इससे देशभर में अफरात-फरी मच गई।

हालांकि, एजेंसी ने करीब 12 मिनट बाद अलर्ट वापस ले लिया। जापान की मौसम एजेंसी ने इस गलती के लिए माफी मांगी है।

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में कामचटका में 1200 से ज्यादा भूकंप दर्ज किए गए थे। इनमें से अधिकांश छोटे-मोटे (मैग्निट्यूड 2.0 से 4.0 के बीच) थे, लेकिन 4.0 या इससे ऊपर के 150 से ज्यादा भूकंप हुए। इस क्षेत्र में पिछले साल 3 बड़े भूकंप 7.0 या उससे अधिक तीव्रता के दर्ज किए गए थे। साल 2025 का सबसे विनाशकारी भूकंप जुलाई को रूस के कामचटका में पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8.8 मापी गई। यह पिछले 10 वर्षों का सबसे बड़ा झटका था। इसने कई देशों को प्रभावित किया। कामचटका प्रशांत महासागर के उस इलाके में है, जिसे 'रिंग ऑफ फायर' कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ऐसा क्षेत्र है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। कामचटका में बार-बार भूकंप आने की मुख्य वजह जमीन के नीचे मौजूद विशाल प्लेटों की हलचल है। यहां प्रशांत प्लेट धीरे-धीरे ओखोत्स्क प्लेट के नीचे खिसक रही है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। दोनों प्लेटों के बीच घर्षण से चट्टानों में दबाव जमा होता रहता है। जब यह दबाव अचानक बाहर निकलता है, तो भूकंप आता है। प्लेटों की इसी हलचल से जमीन के नीचे गर्म पिघला हुआ पदार्थ बनता है, जिसे मैग्मा कहते हैं। यह बाहर निकलता है तो ज्वालामुखी फटता है। यहां कई सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। समुद्र के नीचे तेज भूकंप आने पर सुनामी का खतरा भी रहता है। इस इलाके में जमीन के नीचे प्लेटों की हलचल लगातार जारी रहती है। इसलिए यहां भविष्य में भी भूकंप आने की आशंका बनी रहेगी।



जापान के भूकंप अलर्ट में इतनी बड़ी गलती कैसे हुई?

जापान की भूकंप चेतावनी प्रणाली जमीन पर लगे सेंसर से मिले शुरुआती आंकड़ों के आधार पर भूकंप की तीव्रता और उसके असर का अनुमान लगाती है। यह काम कुछ ही समय में किया जाता है। शुरुआत में आंकड़े अधूरे होने के कारण अनुमान गलत हो सकता है। लेकिन इस बार 9.9 तीव्रता का अलर्ट जारी करना बड़ी चूक थी। इतनी तीव्रता का भूकंप अब तक दर्ज नहीं किया गया है।



जापान में भूकंप के अलर्ट के बाद लोग सड़कों पर बैठ गए।

इनके पास पूरे कागजात नहीं, पकड़े जाने का डर फल-सब्जियों के दाम बढ़ने की आशंका

अमेरिका में 30 हजार भारतीय मजदूरों ने काम छोड़ा

लंदन, एजेंसी

अमेरिका के कैलिफोनिया में करीब 30 हजार भारतीय मजदूरों को खेती का काम छोड़ना पड़ा है। इनमें से कई मजदूरों के पास अमेरिका में रहने और काम करने के पूरे कागजात नहीं हैं।

ऐसे में इमिग्रेशन एजेंसी ICE के छापों और पकड़े जाने के डर से मजदूर काम करने से बच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इससे फल और सब्जियों के दाम 30% से 32% तक बढ़ सकते हैं।

कैलिफोर्निया में प्रवासियों को देश से निकालने की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन करते लोग। तस्वीर 2 दिसंबर 2024 की है।

कैलिफोर्निया में प्रवासियों को देश से निकालने की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन करते लोग। तस्वीर 2 दिसंबर 2024 की है।

अमेरिका में एक लाख भारतीय मजदूर खेती का काम करते हैं

अमेरिका में बिना जरूरी कागजात के रह रहे करीब 7.5 लाख भारतीयों में से लगभग एक लाख खेती से जुड़े काम करते हैं।

ICE की छापेमारी के चलते कैलिफोर्निया से लेकर कैंसस तक कई जगह खेतों में मजदूरों की कमी देखी जा रही है।

वहीं ट्रम्प अवैध प्रवासियों को देश से निकालने की कार्रवाई को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं।

अमेरिका में जरूरी कागजात के बिना रह रहे लोगों को भी कुछ कानूनी अधिकार मिले हैं। लेकिन कई प्रवासियों के लिए इन अधिकारों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है। कई प्रवासियों के पास वकील के पैसे नहीं हैं। ऐसे में उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले बिना ही अमेरिका से निकाला जा सकता है। पॉलिटिको की रिसर्च के मुताबिक, 40 से ज्यादा अदालतें करीब 5 हजार प्रवासियों के पक्ष में फैसला सुना चुकी हैं। इसके बावजूद सरकार इन प्रवासियों को इमिग्रेशन वकील नहीं दे रही है।



कैलिफोर्निया में हजारों लोग हिरासत में

कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। ट्रम्प ने राज्य सरकार पर अवैध प्रवासियों को बचाने का आरोप लगाया है। इसके बाद ट्रम्प ने ICE को वहां कड़ी कार्रवाई करने को कहा।

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो महीनों में हजारों खेत मजदूरों को पकड़कर हिरासत केंद्रों में रखा गया है। कुछ लोगों को देश से निकाला भी गया है।

यूरोप में युवाओं पर बुजुर्ग भारी पड़ रहे



पेंशन पर सरकारी खजाना खर्च जेनजी नौकरी-घर और अच्छी शिक्षा मांग रहे

पेरिस, एजेंसी

पिछले कुछ सालों में Gen Z यानी युवा पीढ़ी एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। बांग्लादेश, नेपाल, पेरू और मेडागास्कर में युवाओं के प्रदर्शनों ने सरकारें गिरा दीं। भारत में भी कई प्रदर्शनों में युवाओं की अहम भूमिका रही है।

अब यूरोप में भी युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। फ्रांस में स्कूलों की बदहाली, स्पेन में बेरोजगारी और ब्रिटेन में पेंशन नीतियों को लेकर नाराजगी है। युवाओं के लिए नौकरी पाना, अच्छी शिक्षा हासिल करना और सस्ता घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है।

यूरोप में इस मुश्किल ने युवाओं और बुजुर्गों के बीच आर्थिक और राजनीतिक टकराव बढ़ा दिया है।



बुजुर्गों की आबादी बढ़ने के साथ राजनीति में उनका प्रभाव भी मजबूत हुआ है। वहीं, युवाओं की संख्या घट रही है। ऐसे में उनके लिए अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना और मुश्किल हो रहा है। फ्रांस में युवाओं के सामने नौकरी की कमी है। बेरोजगारी 20% पहुंच चुकी है। इस साल दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ शून्य रही। दूसरी तरफ, सरकार के कुल खर्च का करीब 25% पेंशन पर जाता है। यानी बजट का बड़ा हिस्सा बुजुर्गों की पेंशन में खर्च हो रहा है। कुछ साल पहले राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल करने का फैसला किया था। इसके खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हुए और सरकार को फैसला निलंबित करना पड़ा। अब पक्ष हो या विपक्ष कोई भी पेंशन में कटौती को लेकर चर्चा भी नहीं करता।

युवा चाहते हैं कि स्कूलों की हालत सुधरे और शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च हो। वामपंथी नेताओं का तर्क है कि पेंशन बचाते हुए शिक्षा का बजट भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि पैसा आएगा कहां से? फ्रांस पर पहले से भारी कर्ज है, और अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने से भी सरकार को खास कमाई नहीं हुई है।

वारदात : इनमें 3 बच्चे, स्थानीय नागरिक ने हमलावर को मार गिराया इस साल स्कूलों में फायरिंग का 26वां मामला

अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी, 4 की मौत

लंदन, एजेंसी

अमेरिका के ओरेगन राज्य के बेंड शहर में गुरुवार को एक स्कूल में गोलीबारी हुई। इसमें 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई।

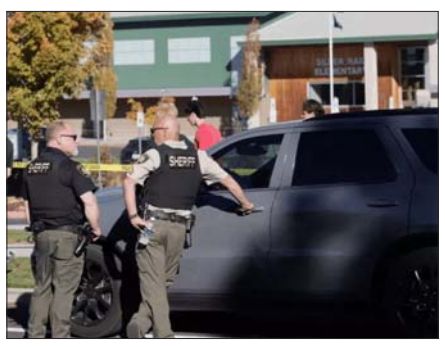
CNN के मुताबिक, हमलावर को एक स्थानीय नागरिक ने गोली मार दी, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर की उम्र करीब 16 साल थी।

एजुकेशन वीक की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में गोलीबारी का यह इस साल का 26वां मामला है।

रॉयटर्स के मुताबिक, सिल्वर रेल एलीमेंट्री स्कूल में किंडरगार्टन से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। स्कूल में करीब 450 छात्र और 40 कर्मचारी हैं।

ओरेगन की गवर्नर टीना कोटेक ने हमलावर को रोकने वाले स्थानीय नागरिक से भी बात की। गवर्नर ने उस नागरिक की तारीफ करते हुए कहा कि उसने बहादुरी से लोगों की जान बचाई। 19 अप्रैल, लुइसियानाः श्रेवपोर्ट में गोलीबारी में 8 बच्चों की मौत हुई। इनमें हमलावर के 7 बच्चे शामिल थे।

9 अक्टूबर, पेंसिल्वेनियाः एरी में एक व्यक्ति ने परिवार के 7 सदस्यों और एक परिचित की हत्या कर दी। बाद में उसने खुदकुशी कर ली। 9 अक्टूबर, जॉर्जियाः डगलस में एक व्यक्ति ने परिवार के 4 सदस्यों की गोली मारकर हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली।





एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया पर बताया कि एजेंसी की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। फिलहाल जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि क्या हमलावर पहले कभी इस स्कूल में पढ़ा था। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है। आने वाले दिनों में घटना से जुड़ी और जानकारी जारी की जाएगी।

मारे गए बच्चे 5 से 11 साल के थे

एसोसिएटेड प्रेस (AP) के मुताबिक, मारे गए बच्चों की उम्र 5, 8 और 11 साल थी। मरने वालों में एक शिक्षक भी शामिल है। इनके परिवारों को जानकारी दे दी गई है। गोलीबारी में घायल 7 साल के एक बच्चे और 54 साल के शिक्षक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रमुख माइक क्रांट्ज ने बताया कि हमलावर बेंड का रहने वाला था। उसने स्कूल के बंद दरवाजों पर गोली चलाकर अंदर घुसने का रास्ता बनाया था।

सोना आज 572 रुपए महंगा, 1.47 लाख पहुंचा

चांदी 2 हजार चढ़कर 2.10 लाख पहुंची

नई दिल्ली, एजेंसी

सोने-चांदी की कीमतों में आज 16 अक्टूबर को तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 572 रुपए चढ़कर 1,46,514 रुपए पहुंच गया है।

इससे पहले 15 अक्टूबर को यह 1,45,942 रुपए पर था। वहीं, एक किलो चांदी 2,037 रुपए चढ़कर 2.10 लाख रुपए पर हो गई है, जो गुरुवार को 2.08 लाख रुपए पर थी। ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटीः एक शहर से दूसरे शहर सोना ले जाने में ईंधन और सुरक्षा खर्च जुड़ता है, जिससे दूरी बढ़ने पर दाम बढ़ते हैं। खरीदारी की मात्राः दक्षिण भारत में ज्यादा खपत (करीब 40%) के कारण ज्वेलर्स बड़ी खरीद करते हैं, लेकिन छूट का फायदा सीमित रहता है।



लोकल ज्वेलरी एसोसिएशनः राज्य और शहर के ज्वेलरी एसोसि-एशन स्थानीय मांग-सप्लाई के आधार पर रेट तय करते हैं।

पुराना स्टॉक और खरीद मूल्यः ज्वेलर्स का खरीदी रेट तय करता है कि वे ग्राहकों को कितनी कीमत में बेचेंगे। इस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 13,319 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं, चांदी 20,108 रुपए सस्ती हुई है।

31 दिसंबर 2025 को 10g सोना 1.33 लाख रुपए था, जो अब 1.47 लाख रुपए पहुंच गया है।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676